



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]
No. 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 1975/चैत्र 22, 1897
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 1975/CHAITRA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II--Section 3--Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1975

M/s. Ram Kishan Kulwant Rai, Calcutta, in the court of
the 11th Metropolitan Magistrate, Calcutta.

[No. 225/13/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1975

का० प्रा० 1131 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे० एन० घोष, एडवोकेट और श्री प्रदीप मुल्लिक, एडवोकेट को इलेक्चिव मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में मैसर्स राम किशन कुलवंत राय, कलकत्ता के बिरुद्ध केस नं० 1/69-एस० आई० यू० में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फाल्गुनी-चैत्र, 1975 को पेश करने के लिये, विशेष-सौक-अभिबीजक नियुक्त करती है।

[सं० 225/13/75-ए०बी०डी०-2]

बी० सी० बंजानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 21st March, 1975

S.O. 1131.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri J. N. Ghosh and Pradosh Mullick, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution of the accused, in case RC No. 1/69-SIU against

5 GI/75-1

का० प्रा० 1132.—जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग 2-खंड 3-उपखंड (ii), दिनांक 16 फरवरी, 1971 में प्रकाशित, भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) की अधिसूचना संख्या 375/31/71-ए० बी० डी०-3 (का० प्रा० 3863), दिनांक 16 फरवरी, 1971 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में '31 मार्च, 1975 तक' शब्दों, शर्कों और अक्षरों के स्थान पर '30 सितम्बर, 1975 तक' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या 381/21/71/ए० बी० डी०-3]

धार० सी० मिश्र, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th March, 1975

S.O. 1132.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further

(1453)

amendment in the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) No. 375/31/71-AVD.III (S.O. 3863), dated the 16th October, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th October, 1971, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the words, figures and letters "by the 31st March, 1975" the words, figures and letters "by the 30th September, 1975" shall be substituted.

[No. 381/21/71-AVD. III]

R. C. MISRA, Jt. Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1975

क्र० प्र० 1133.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन के लिये 118-धेनकनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पूरन चन्द्र साहू, धेनकनाल मीना बाजार, धेनकनाल (उड़ीसा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घोष बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पत्ति सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री पूरन चन्द्र साहू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उड़ीसा-वि० सं० 118/74]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1975

S.O. 1133.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Purna Chandra Sahoo, Dhenkanal Minabazar, Dhenkanal (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from 118-Dhenkanal constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Purna Chandra Sahoo to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. OR-LA/118/74]

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1975

क्र० प्र० 1134.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए कुलियाना

(प्र० ज० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री परशुराम सिंह, ग्राम तथा पञ्चायत भौतमाबिला, जिला मयूरभंज, (उड़ीसा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घोष बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पत्ति सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री परशुराम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उड़ीसा वि० सं० 6/74]

ORDER

New Delhi, the 21st March, 1975

S.O. 1134.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Parsuram Singha, Village and P. O. Baunsabila, District Mayurbhanj, (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Kullana (ST) constituency, held in February 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And, whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Parsuram Singha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/6/74]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1975

क्र० प्र० 1135.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उड़ीसा सरकार के परामर्श से सीजे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट अपनी अधिसूचना सं० 282/उड़ीसा/73, तारीख 31 दिसम्बर, 1973 के साथ पठित परिसीमन आयोग द्वारा अपने आदेश सं० 9 द्वारा यथा अवधारित उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदनिहित करता है।

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1. मयूरभंज (प्र० ज० जा०)	कलक्टर, मयूरभंज।
2. बालासोर	कलक्टर, बालासोर।
3. तड़क (प्र० जा०)	कलक्टर, बालासोर।
4. जाजपुर (प्र० जा०)	कलक्टर, कटक।
5. केन्द्रापारा	कलक्टर, कटक।

1	2
6. कटक	कलक्टर, कटक ।
7. जगत सिंहपुर	कलक्टर, कटक ।
8. पुरी	कलक्टर, पुरी ।
9. भुवनेश्वर	कलक्टर, पुरी ।
10. आसका	कलक्टर, गंजाम ।
11. बरहामपुर	कलक्टर, गंजाम ।
12. कोरापुर (अ० ज० जा०)	कलक्टर, कोरापुट ।
13. नौरंगपुर (अ० ज० जा०)	कलक्टर, कोरापुट ।
14. कालाहण्डी	कलक्टर, कालाहण्डी ।
15. फुल बनी (अ० जा०)	कलक्टर, फुलबनी ।
16. बोलंगीर	कलक्टर, बोलंगीर ।
17. सम्बलपुर	कलक्टर, सम्बलपुर ।
18. देवगढ़	कलक्टर, सम्बलपुर ।
19. धेन्कानल	कलक्टर, धेन्कानल ।
20. सुन्दरगढ़ (अ० ज० जा०)	कलक्टर, सुन्दरगढ़ ।
21. क्योन्मर (अ० ज० जा०)	कलक्टर, क्योन्मर ।

[सं० 434/उड़ीसा/75]

New Delhi, the 22nd March, 1975

S. O. 1135.—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Orissa, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa, as determined by the Delimitation Commission in its Order No. 9 read with its notification No. 282/OR/73 dated the 31st December, 1973, and as specified in column 1 of the said Table against such officer of Government :—

TABLE

Serial No. and name of the Constituency	Returning Officer
1	2
1. Mayurbhanj (ST)	Collector, Mayurbhanj
2. Balasore	Collector, Balasore
3. Bhadrak (SC)	Collector, Balasore
4. Jajpur (SC)	Collector, Cuttack
5. Kendrapara	Collector, Cuttack
6. Cuttack	Collector, Cuttack
7. Jagatsinghpur	Collector, Cuttack
8. Puri	Collector, Puri
9. Bhubaneswar	Collector, Puri
10. Aska	Collector, Ganjam
11. Berhampur	Collector, Ganjam
12. Koraput (ST)	Collector, Koraput
13. Nowrangpur (ST)	Collector, Koraput
14. Kalahandi	Collector, Kalahandi
15. Phulbani	Collector, Phulbani
16. Bolangir	Collector, Bolangir
17. Sambalpur	Collector, Sambalpur
18. Deogarh	Collector, Sambalpur
19. Dhenkanal	Collector, Dhenkanal
20. Sundargarh (ST)	Collector, Sundargarh
21. Keonjhar (ST)	Collector, Keonjhar

[No. 434/OR/75]

का० प्रा० 1136.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 53) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर या आफिसरों को ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसरों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 282/उड़ीसा/73, तारी 31 दिसम्बर, 1973 द्वारा यथा भवधारित उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1. 1-मयूरभंज (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, मयूरभंज । 2. उप-खण्ड आफिसर, पंचपीर । 3. उप-खण्ड आफिसर, बामनघाटी । 4. उप-खण्ड आफिसर, सदर, बाड़ीपाया । 5. उप-खण्ड आफिसर, कपटीपाड़ा ।
2. बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालासोर । 2. उप-खण्ड आफिसर, सदर, बाड़ीपाड़ा । 3. उप-खण्ड आफिसर, कपटीपाड़ा । 4. उप-खण्ड आफिसर, सदर, बालासोर ।
3. 3-भाद्रक (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालासोर । 2. उप-खण्ड आफिसर, सदर, बालासोर । 3. उप-खण्ड आफिसर, नीलगिरि । 4. उप-खण्ड आफिसर, भाद्रक ।
4. 4-जाजपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. उप-खण्ड आफिसर, जाजपुर । 3. उप-खण्ड आफिसर, केन्द्रपारा ।
5. 5-केन्द्रपारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. जिला विकास आफिसर, कटक । 3. उप-खण्ड आफिसर, केन्द्रपारा । 4. उप-खण्ड आफिसर, सदर, कटक । 5. उप-खण्ड आफिसर, जगतसिंहपुर ।
6. 6-कटक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. जिला विकास आफिसर, कटक । 3. उप-खण्ड आफिसर, सदर, कटक । 4. उप-खण्ड आफिसर, बंकी । 5. उप-खण्ड आफिसर, अथगढ़ ।
7. 7-जगतसिंह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुरी । 3. जिला विकास आफिसर, कटक । 4. उप-खण्ड आफिसर, जगतसिंहपुर । 5. उप-खण्ड आफिसर, सदर, कटक । 6. उप-खण्ड आफिसर, सदर, पुरी ।

1	2
8. 8-पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुरी। 2. उप-खण्ड आफिसर, सबर, पुरी। 3. उप-खण्ड आफिसर, भुवनेश्वर। 4. उप-खण्ड आफिसर, खुर्दा। 5. उप-खण्ड आफिसर, नयागढ़।
9. 9-भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुरी। 2. उप-खण्ड आफिसर, भुवनेश्वर। 3. उप-खण्ड आफिसर, खुर्दा। 4. उप-खण्ड आफिसर, नयागढ़।
10. 10-भासका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, गंजम। 2. उप-खण्ड आफिसर, भंजानगर। 3. उप-खण्ड आफिसर, चक्रपुर।
11. 11-बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, गंजम। 2. उप-खण्ड आफिसर, चक्रपुर। 3. उप-खण्ड आफिसर, बरहामपुर। 4. उप-खण्ड आफिसर, परलाखेमण्डी।
12. 12-कोरापुट (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोरापुट। 2. उप-खण्ड आफिसर, गुनुपुर। 3. उप-खण्ड आफिसर, रायगाडा। 4. उप-खण्ड आफिसर, कोरापुट। 5. उप-खण्ड आफिसर, जयपोर।
13. 13-मौरंगपुर (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोरापुट। 2. उप-खण्ड आफिसर, मलकानगिरि। 3. उप-खण्ड आफिसर, जयपोर। 4. उप-खण्ड आफिसर, मौरंगपुर।
14. 14-कालाहण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कालाहण्डी। 2. उप-खण्ड आफिसर, नवापारा। 3. उप-खण्ड आफिसर, धर्मगढ़। 4. उप-खण्ड आफिसर, सबर, भवानी पटना।
15. 15-फूलबनी (अ० जा०) [संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, फूलबनी। 2. उप-खण्ड आफिसर, भंजानगर। 3. उप-खण्ड आफिसर, बल्लीगुडा। 4. उप-खण्ड आफिसर, फूलबनी। 5. उप-खण्ड आफिसर, बौध। 6. उप-खण्ड आफिसर, सोनैपुर।
16. 16-बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, बोलंगीर। 2. उप-खण्ड आफिसर, नवापारा। 3. उप-खण्ड आफिसर, तिल्लिगाढ़। 4. उप-खण्ड आफिसर, पटनागढ़। 5. उप-खण्ड आफिसर, जोलंगीर।
17. 17-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, सम्बलपुर। 2. उप-खण्ड आफिसर, पदमपुर। 3. उप-खण्ड आफिसर, बरागढ़। 4. उप-खण्ड आफिसर, सबर, सम्बलपुर। 5. उप-खण्ड आफिसर, रेराबोल।

1	2
18. 18-देवगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, सम्बलपुर। 2. अपर जिला मजिस्ट्रेट, धेन्कानल। 3. उप-खण्ड आफिसर, पल्लाहारा। 4. उप-खण्ड आफिसर, तालचेर। 5. उप-खण्ड आफिसर, सदर सम्बलपुर। 6. उप-खण्ड आफिसर, कुशिपदा। 7. उप-खण्ड आफिसर, देवगढ़।
19. 19-धेन्कानल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, धेन्कानल। 2. उप-खण्ड आफिसर, सोनेपुर। 3. उप-खण्ड आफिसर, अठमल्लिक। 4. उप-खण्ड आफिसर, धंगुल। 5. उप-खण्ड आफिसर, हिल्डोल। 6. उप-खण्ड आफिसर, धेन्कानल। 7. उप-खण्ड आफिसर, कामाख्या नगर।
20. 20-मुन्वरगढ़ (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, मुन्वरगढ़। 2. अपर जिला मजिस्ट्रेट, राउरकेला। 3. उप-खण्ड आफिसर, सदर, मुन्वरगढ़। 4. उप-खण्ड आफिसर, पनपोश। 5. उप-खण्ड आफिसर, बोनाई।
21. 21-क्योंन्तर (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, क्योंन्तर। 2. उप-खण्ड आफिसर, पंचपीर। 3. उप-खण्ड आफिसर, चम्पुआ। 4. उप-खण्ड आफिसर, क्योंन्तर। 5. उप-खण्ड आफिसर, भानन्पुर।

[सं० 434/उड़ीसा/75(1)]

ए० एम० सैन, सचिव

S. O. 1136.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission hereby appoints the officer or officers of Government of Orissa as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa, as determined by the Delimitation Commission in its notification No. 282/OR/73, dated the 31st December, 1973, and as specified in column 1 of the said Table against such officer or officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer or Officers	Officer
1	2	
1. Returning Officer of 1-Mayurbhanj (ST) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Mayurbhanj.	Officer,
	2. Sub-Divisional Panchpir,	Officer,
	3. Sub-Divisional Bamanghaty.	Officer,
	4. Sub-Divisional Sadar, Baripada.	Officer,
	5. Sub-Divisional Kaptipada.	Officer,

1	2	1	2
2. Returning Officer of 2-Balasore Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Balasore. 2. Sub-Divisional Officer, Sadar, Baripada. 3. Sub-Divisional Officer, Kaptipada. 4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Balasore.	11. Returning Officer of 11-Berhampur Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Ganjam. 2. Sub-Divisional Officer, Chatrapur. 3. Sub-Divisional Officer, Berhampur. 4. Sub-Divisional Officer, Parlakhemundi.
3. Returning Officer of 3-Bhadrak (SC) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Balasore. 2. Sub-Divisional Officer, Sadar, Balasore. 3. Sub-Divisional Officer, Nilgiri. 4. Sub-Divisional Officer, Bhadrak.	12. Returning Officer of 12-Koraput (ST) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Koraput. 2. Sub-Divisional Officer, Gunupur. 3. Sub-Divisional Officer, Rayagada. 4. Sub-Divisional Officer, Koraput. 5. Sub-Divisional Officer, Jeypore.
4. Returning Officer of 4-Jajpur (SC) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Cuttack. 2. Sub-Divisional Officer, Jajpur. 3. Sub-Divisional Officer, Kendrapara.	13. Returning Officer of 13-Nowrangpur (ST) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Koraput. 2. Sub-Divisional Officer, Malkangiri. 3. Sub-Divisional Officer, Jeypore. 4. Sub-Divisional Officer, Nowrangpur.
5. Returning Officer of 5-Kendrapara Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Cuttack. 2. District Development Officer, Cuttack. 3. Sub-Divisional Officer, Kendrapara. 4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Cuttack. 5. Sub-Divisional Officer, Jagatsingpur.	14. Returning Officer of 14-Kalahandi Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Kalahandi. 2. Sub-Divisional Officer, Nawapara. 3. Sub-Divisional Officer, Dharamgarh. 4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Bhawanipatna.
6. Returning Officer of 6-Cuttack Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Cuttack. 2. District Development Officer, Cuttack. 3. Sub-Divisional Officer, Sadar, Cuttack. 4. Sub-Divisional Officer, Banki. 5. Sub-Divisional Officer, Athgarh.	15. Returning Officer of 15-Phulbani (SC) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Phulbani. 2. Sub-Divisional Officer, Bhanjanagar. 3. Sub-Divisional Officer, Balliguda. 4. Sub-Divisional Officer, Phulbani. 5. Sub-Divisional Officer, Boudh. 6. Sub-Divisional Officer, Sonepur.
7. Returning Officer of 7-Jagatsinghpur Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Cuttack. 2. Additional District Magistrate, Puri. 3. District Development Officer, Cuttack. 4. Sub-Divisional Officer, Jagatsinghpur. 5. Sub-Divisional Officer, Sadar, Cuttack. 6. Sub-Divisional Officer, Sadar, Puri.	16. Returning Officer of 16-Bolangir Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Bolangir. 2. Sub-Divisional Officer, Nawapara. 3. Sub-Divisional Officer, Titilagarh. 4. Sub-Divisional Officer, Patnagarh. 5. Sub-Divisional Officer, Bolangir.
8. Returning Officer of 8-Puri Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Puri. 2. Sub-Divisional Officer, Sadar, Puri. 3. Sub-Divisional Officer, Bhubaneswar. 4. Sub-Divisional Officer, Khurda. 5. Sub-Divisional Officer, Nayagarh.	17. Returning Officer of 17-Sambalpur Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Sambalpur. 2. Sub-Divisional Officer, Padmapur. 3. Sub-Divisional Officer, Baragarh. 4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Sambalpur. 5. Sub-Divisional Officer, Rairakhol.
9. Returning Officer of 9-Bhubaneswar Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Puri. 2. Sub-Divisional Officer, Bhubaneswar. 3. Sub-Divisional Officer, Khurda. 4. Sub-Divisional Officer, Nayagarh.	18. Returning Officer of 18-Deogarh Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Sambalpur. 2. Additional District Magistrate, Dhenkanal. 3. Sub-Divisional Officer, Pallahara. 4. Sub-Divisional Officer, Talcher. 5. Sub-Divisional Officer, Sadar, Sambalpur.
10. Returning Officer of 10-Aska Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Ganjam. 2. Sub-Divisional Officer, Bhanjanagar. 3. Sub-Divisional Officer, Chatrapur.		

New Delhi, the 21st March, 1975

1	2
	6. Sub-Divisional Officer, Kuchinda.
	7. Sub-Divisional Officer, Deogarh.
19. Returning Officer of 19-Dhenkanal Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate Dhenkanal 2. Sub-Divisional Officer, Sonapur. 3. Sub-Divisional Officer, Athamallik. 4. Sub-Divisional Officer, Angul. 5. Sub-Divisional Officer, Hindol. 6. Sub-Divisional Officer, Dhenkanal. 7. Sub-Divisional Officer, Kamakhyanagar.
20. Returning Officer of 20-Sundargarh (ST) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Sundargarh. 2. Additional District Magistrate Raurakela. 3. Sub-Divisional Officer, Sadar, Sundargarh. 4. Sub-Divisional Officer, Panposh. 5. Sub-Divisional Officer, Bonai.
21. Returning Officer of 21-Koonjhar (ST) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Keonjhar. 2. Sub-Divisional Officer, Panchpir. 3. Sub-Divisional Officer, Champua. 4. Sub-Divisional Officer, Keonjhar. 5. Sub-Divisional Officer, Anandapur.

[No. 434/OR/75(1)]

A.N. SEN, Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1975

का० प्रा० 1137.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/केरल/74(4), दिनांक 18 नवम्बर, 1974 में आगे निम्नलिखित संशोधन और किये जायेंगे, अर्थात्:—

उक्त सूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—

(क) मद सं० 14 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, “8-सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (साधारण) क्वीकोन” प्रविष्टि जोड़ी जायेगी; तथा

(ख) मद सं० 17 के सामने विद्यमान प्रविष्टि सं० 2 के स्थान पर “2-वन खंड पवाधिकारी, कोन्नी” और “3-वन खंड पवाधिकारी, पुनानुर” प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी तथा उसके पश्चात्पूर्वी प्रविष्टि सं० 3 से 6 तक की क्रमशः सं० 4 से 7 तक के रूप में संशोधित कर दिया जायेगा।

[सं० 434/केरल/74(4)]

श्री० नागसूब्रह्मण्यन, सचिव।

S.O. 1137.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/KL/74(4) dated 18 November, 1974, namely:—

In column 2 of the Table appended to the said notification—

(a) after the existing entries against item No. 14, the entry “8. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Quilon” shall be added; and

(b) for the existing entry at serial No. 2 against item No. 17, the entries “2. Divisional Forest Officer, Konni” and “3. Divisional Forest Officer, Punalur” shall be substituted and subsequent entries numbered 3 to 6 be renumbered as 4 to 7.

[No. 434/KL/74(A)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1975

का० प्रा० 1138.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 सितम्बर, 1974 को “नागा राष्ट्रीय परिषद्”, “नागालैण्ड की संघीय सरकार”, “नागा सेना”, “किमहाबो” (उच्च सदन) और “तानार होहो” (प्रतिनिधि-सभा) और “संघ उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन “अन्य निकायो” को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 सितम्बर, 1974 को, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित किया जिसके पीठासीन अधिकारी गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीन न्याय-मूर्ति श्री० पाठक होंगे;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना को 26 सितम्बर, 1974 को उक्त अधिकरण को यह न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन से निर्दिष्ट किया था कि क्या उक्त संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे;

और यतः उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 फरवरी, 1975 को एक आदेश किया;

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिकरण के उक्त आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है अर्थात्:—

आदेश

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

(अंग्रेजी में प्रकाशित अधिसूचना देखिय)

[सं० 3-14015/43/74 एन० ई०-1]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th March, 1975

S.O. 1138.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967),

declared on the 1st September, 1974, the "Naga National Council", "Federal Government of Nagaland", "Naga Army", "Kimhao" (Upper House) and "Tatar Hoho" (Assembly of Representatives) and "Federal Supreme Court and other bodies under it," to be unlawful associations;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted on the 16th September, 1974, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Mr. Justice D. Pathak, Judge of Gauhati High Court;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 26th September, 1974, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said associations unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an order on the 26th February, 1975;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Order of the said Tribunal, namely:—

ORDER

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)

TRIBUNAL

Reference made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act 37 of 1967).
IN RE: NAGA NATIONAL COUNCIL AND OTHER ASSOCIATIONS.

PRESENT:

The Hon'ble Mr. Justice D. Pathak.
For the Naga National Council and other associations—
None appears.

For the Central Government—Br. B. K. Das, Mr. H. K. Sema, Advocate.

Place of sitting—Tripura House, Golf Links, New Delhi.

Dates of hearing—14th, 18th, 19th and 20th February, 1975.

Date of order—26th February, 1975.

ORDER

The Central Government (hereinafter referred to as the Government) have by their letter No. III-14015/43/74-NE dated 26th September, 1974, made this reference under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act 37 of 1967) (hereinafter called the Act to the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (for the sake of brevity referred to hereinafter as the Tribunal), constituted under Section 5(1) of the Act, by the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 547(E) dated 16th September, 1974, to adjudicate whether or not, there is sufficient cause for declaring the Naga National Council (for brevity hereinafter referred to as N.N.C.) and other bodies mentioned in the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 1st September, 1974, under Section 3(1) of the Act.

2. The Act empowers the Central Government to declare unlawful any association if it is of opinion that such association is, or has become unlawful. The association can be declared unlawful by a notification in the official Gazette. Sub-section (2) of Section 3 of the Act required that every such notification issued under Section 3 of the Act shall specify the grounds on which it is issued and such other particulars as the Central Government may consider necessary. Sub-section (3) of Section 3 provides that no such notification shall have effect until the Tribunal as by an order made under section 4, confirmed the declaration made therein and

the said order is published in the Official Gazette. The proviso to sub-section (3) of Section 3 however, confers special powers on the Central Government to give immediate effect to the notification if in its opinion circumstances exist which render it necessary to declare an association to be unlawful with immediate effect, for reasons to be stated in writing. Under Section 4 sub-section (1), the Central Government is required to make a reference to the Tribunal within thirty days from the date of publication of the notification for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring an association unlawful. Section 4 sub-section (2) lays down that on receipt of the reference under sub-section (1), the Tribunal has to effect notice in writing to the association to show cause within thirty days from the date of service of notice, why the association should not be declared unlawful. Sub-section (3) of Section 4 provides that after considering the cause, if any shown, by the association, the Tribunal shall hold an inquiry in the manner specified in section 9 and after calling for any further information as it may consider necessary decide whether or not there is sufficient cause for declaring the association to be unlawful. This sub-section further requires that the Tribunal must give its decision within six months from the date of issue of the notification. This provision further confers power on the Tribunal either to confirm the declaration made in the notification or to cancel the same. Sub-section (5) of Section 5 gives plenary powers to the Tribunal to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions including the place or places at which it holds its sittings. This provision is, however, subject to Section 9 of the Act which is a specific section. This section lays down the procedure to be adopted by the Tribunal in holding the inquiry in a reference made by the Central Government. According to Section 9 the procedure to be followed by the Tribunal in holding any inquiry shall, so far as may be, be the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, for the investigation of claims and the decision of the Tribunal shall be final. So, these are some of the provisions with which we are concerned in the present inquiry. The Naga National Council and other bodies mentioned in the schedule to the notification namely, (1) Federal Government of Nagaland, (2) Naga Army, (3) Kimhao (Upper House) and Tatar Hoho (Assembly of Representatives), (4) Federal Supreme Court and other bodies under it, were declared to be an unlawful association by notification No. S.O. 519(E) dated 1st September, 1974, issued by the Central Government and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii). The notification referred to above runs thus:—

"Whereas the "Naga National Council" (hereinafter referred to as the Council), which had openly declared as its objective the formation of an independent Nagaland, comprising the State of Nagaland and the adjacent Naga-inhabited areas of Assam, Manipur and Arunachal Pradesh (hereinafter referred as the said areas),—

- (i) has been continuing its attitude and policy to achieve the said objective and to bring about secession of the said areas from the Union of India,
- (ii) has been employing the so-called Naga Army and the other organisations specified in the Schedule below, set up by the Council, to further, its objective aforesaid;
- (iii) has, in furtherance of the said objective, been employing the so-called Naga Army in attacking the Security Forces, the Civil Government and the citizens in the said areas and indulging in acts, such as arson, looting, intimidation of the civil population and forcible recruitment, collection of funds and foodstuffs;
- (iv) has, to achieve its objective aforesaid, maintained contacts, through the so-called Federal Government of Nagaland, with foreign countries with a view to securing financial and armed assistance and training facilities for the so-called Naga Army, and has secured such assistance;
- (v) has been engaging in violent activities with increasing boldness and aggressiveness as is evidenced by increased number of incidents of ambushes and attacks on Security Forces and Security Posts.

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Council and the other organisations specified in the Schedule below are unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks of the so-called Naga Army on the Security Forces and on the civil population, it is necessary to declare the Council and the other organisations aforesaid to be unlawful with immediate effect.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the "Naga National Council" and the other organisations specified in the Schedule below, to be unlawful associations, and in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

1. Federal Government of Nagaland.
2. Naga Army.
3. Kimhao (Upper House) and Tatar Hoho (Assembly of Representatives):
4. Federal Supreme Court and other bodies under it."

3. The tribunal received the reference on 28-9-74 which is within one month from the date of publication of the notification under consideration under section 3(1) of the Act.

The Government along with the reference sent the notification under section 3(1) and also the statement of facts on which the grounds specified in the notification are based in compliance with rule 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968, (hereinafter called the Rules). After receipt of the reference the Tribunal on 28-9-74 issued notices on the Naga National Council, Federal Government of Nagaland, Naga Army Kimhao (Upper House and Tatar Hoho (Assembly of Representatives), Federal Supreme Court and other bodies under it, to show cause, in writing, within thirty days from the date of service of the notice, why the said association should not be declared unlawful. This notice calling upon the N.N.C. and other bodies to show cause was broadcast by All India Radio, Gauhati, on 4-10-74, by All India Radio, Imphal on 5-10-74, by All India Radio, Tezu on 11-10-74 and by All India Radio, Kohima on 7-10-74. The notices were proclaimed in the North Cachar Hills on 16-10-74 where the Naga hostile activities were predominant earlier in that district. These notices were also hung in the Notice Board of the Deputy Commissioner, Cachar on 7-11-74. The service of notices was effected under Rule 6 of the Rules and also under Rule 4(a) of the Rules. Although the notices have been served on the N.N.C. and other bodies concerned and more than thirty days have elapsed, from the date of service of the notices, none showed cause for the N.N.C. and other bodies declared unlawful. Accordingly, on 3-1-75 the Tribunal fixed the date of hearing on 14th February, 1974 at 11 A.M. at Tripura House, Golf Links in New Delhi. The date of inquiry was notified in the Assam Tribune, Gauhati, the Nagaland Times, Dimapur and the Eastern Standard, Imphal, by the Tribunal.

4. On behalf of the Central Government Mr. B. K. Das, Advocate assisted by Mr. H. K. Sema, advocate appeared. The N.N.C. and other bodies affected by the notification neither showed cause nor appeared before the Tribunal at the time of hearing. The Central Government filed an affidavit in support of the action taken under section 3(1) of the Act declaring the N.N.C. and other bodies unlawful.

5. The facts appearing from this statement sent along with the reference as well as the affidavit filed by the Government may be summarised as follows. The Naga National Council and other associations namely, Federal Government of Nagaland, Naga Army, Kimhao (Upper House), Tatar Hoho (Assembly of Representatives), Federal Supreme Court and other bodies under it, were declared as unlawful asso-

ciations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) in the notification issued on September 1, 1972 by the Central Government under the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act. As required under the law, materials in support of the notification was furnished to the Tribunal set up under the Unlawful Activities Act for adjudication. This notification issued on September 1, 1972, was confirmed by the Tribunal on February 13, 1973. The case of the Central Government is that even after the N.N.C. and other organisations were declared as unlawful Associations on September 1, 1972, there has been no change in their attitude and policy. They continue to maintain that Nagaland was an independent country where India has committed an aggression. The Constitution of the Federal Government of Nagaland known as the "Yehzabo" defines the territory of Nagaland comprising all the territories inhabited by the indigenous Naga tribes and such other territories as the "Tatar Hoho" may, by law, admit on such terms and conditions as it deems fit. Based on this definition, the Federal Government of Nagaland includes, besides the State of Nagaland, areas inhabited by Nagas in Arunachal Pradesh, North Cachar Hills and Sibsagar district of Assam, some parts of Manipur as also some Naga-inhabited parts of Burma as constituent parts of "Greater Nagaland". According to the "Yehzabo" (1968), the Naga National Council shall be the only recognised political institution in Nagaland. The so-called Federal Government formed by the Naga underground under their Constitution continues to function under the self-styled President, Zashel Huiire, with all the paraphernalia of usual civil and military administration. That there has been no change in their attitude and policy of armed struggle for independence would also be evident from the activities of the Naga underground during the two years following their being declared unlawful on September 1, 1972. In furtherance of their objective to form an independent Nagaland and secede the areas claimed to comprise "independent Nagaland", they continued to employ the so-called "Naga Army" in attacking the Security Forces, the civil government and the citizens and indulged in acts of arson, looting, intimidation of the civil population, forcible recruitment, collection of taxes and other provisions. They have accordingly been engaging in violent activities with increasing boldness and aggressiveness as would be evident from increased number of ambushes and attacks on Security Forces and Security posts. After the initial setback on being declared unlawful from September 1, 1972, the Naga underground reorganised themselves and intensified their activities which resulted in a spurt in violent activities in Nagaland during 1973. In a letter dated October 16, 1972, addressed to the so-called C-in-C of the Naga Army, Zashel Huiire accused the Government of India of committing aggression and he directed the Naga Army to prepare and defend the homeland. In an extraordinary "Ahza" (order) issued on July 2, 1973, Vivalie Motha, the self-styled C-in-C of the Naga Army, directed all Unit Commanders of the Naga Army to chalk out a fresh fighting programme and resume violent activities in the form of attacking enemy posts or ambush, obstruct the enemy communication and damage any properties of the enemy with effect from August 1, 1973. In a letter dated November 16, 1973, the self-styled Home Minister of the Federal Government of Nagaland, namely, Biseto Medom, accused India of criminal aggression and warned the Naga people against participating in the Indian sponsored elections which, it was pointed out, would constitute outright high treason. The Naga underground indulges in widespread violence and terrorist activities both on the eve of and during the general elections in Nagaland in February, 1974. Between January 1 and February 11, 1974, they were responsible for 10 violent incidents (1 in January and the remaining 9 in February) in which 11 (9 Security Forces and 2 civilians) persons were killed and 10 (8 security forces and 2 civilians) persons were injured. The Naga underground also indulged in 12 violent incidents between February 12 and 16 (during the elections) in which 9 (6 security forces and 3 civilians) persons were killed and 9 other security forces personnel injured.

6. The Government in their statement has given details of some of the incidents occurred after 1st September, 1972 till August 31, 1974. From the case of the Government it further appears that the Naga underground who commenced their insurgency in the fifties of the century, have sustained themselves over the years with considerable foreign assistance, mainly from Pakistan and China, both in the form of finance as well as in arms aid and training. The case of the Government is that the Naga underground organisation has not

only" remained active after they were declared unlawful in 1972, but they have on the other hand continued to pursue their secessionist objectives. According to the Government there has been no change whatsoever in their basic objective in bringing about secession in Nagaland and disrupting the sovereignty and territorial integrity of India and they have continued to adopt illegal and most violent methods to achieve their objective. They further aver that the N.N.C. and other bodies still got links with foreign powers, and they are still committed to continue insurgency till its political objectives are achieved.

7. After going through the case of the Government and hearing the learned counsel appearing on behalf of the Government, the following two issues were framed.

1. Whether or not, there is sufficient cause for declaring the associations, namely :—

- (a) The Naga National Council,
- (b) Federal Government of Nagaland,
- (c) Naga Army,
- (d) Kimhao (Upper House) and Tatar Hobo (Assembly of Representatives),
- (e) Federal Supreme Court and other bodies under it, to be unlawful under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 ?

2. Whether the declaration made under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act of 1967, bearing notification No. S.O. 519(E) published in the Gazette of India, Extraordinary dated New Delhi, 1-9-1974 may be confirmed or is liable to be cancelled ?

In support of their case the Government have examined three witnesses and have filed a large number of documents.

8. Before analysing the evidence adduced by the Government to prove their case, it is apposite to examine the ambit and scope of Section 2 as also the nature and extent of the powers conferred on the Tribunal under Section 4 of the Act. The evidence will have to be scrutinised in the light of the aforesaid provisions with a view to finding out as to whether or not the N.N.C. and other bodies fall within the mischief of Section 2(b), (d), (g) and (f) of the Act. The Preamble of the Act runs as follows :

"An Act to provide for the more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for matters connected therewith."

On reading the Preamble it seems clear that the intention of the Parliament was to provide a preventive legislation in order to arrest unlawful activities of individuals and associations which fell within the ambit and purview of the definition given in Section 2(b), (d), and (f) of the Act. Section 2(b) reads :

"Cession of a part of the territory of India" includes admission of the claim of any foreign country to any such part."

Section 2(d) reads :

"Secession of a part of the territory of India from the Union" includes the assertion of any claim to determine whether such part will remain a part of the territory of India."

Section 2(f) reads :

"Unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),—

- (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession ;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India."

Section 4 of the Act reads as follows :

"(1) Where any association has been declared unlawful by a notification issued under sub-section (1) of Section 3, the Central Government shall, within thirty days from the date of the publication of the notification under the said sub-section, refer the notification to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful.

(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal shall call upon the association affected by notice in writing to show cause, within thirty days from the date of the service of such notice, why the association should not be declared unlawful.

(3) After considering the cause, if any, shown by the association or the office-bearers or members thereof, the Tribunal shall hold an inquiry in the manner specified, in section 9 and after calling for such further information as it may consider necessary from the Central Government or from any office-bearer or member of the association, it shall decide whether or not there is sufficient cause for declaring the association to be unlawful and make, as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date of the issue of the notification under sub-section (1) of section 3, such order as it may deem fit either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same.

(4) The order of the Tribunal made under sub-section (3) shall be published in the Official Gazette."

9. Mr. B. K. Das, the learned counsel for the Central Government in support of his argument refers to a judgment in Case No. UAPT/1 of 1971, Central Government versus The All Jammu and Kashmir Plebiscite Front published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3 Sub-section (ii) dated July 1, 1971, where the Tribunal had to interpret the aforesaid provisions of the Act and the learned counsel adopts for his arguments the following passages,

"It may be pertinent to note that the word 'cession' as defined in 2(b), has an absolutely different conception and a separate connotation that 'secession' which is defined in 2(d) of the Act, Cession implies the giving up or ceding a part of the territory of India and definition is wide enough to include within its ambit admission of the claim of any foreign country to any such part. In other words, if an association or an individual either supports or sponsors or advocates ceding a part of the territory of India to some country or either expressly or impliedly admits the claim of any foreign country to such part the said individual or association clearly falls within the mischief of section 2(d). As regards the words 'secession' it includes the assertion of any claim to determine whether such part will remain a part of the territory of India. The word 'includes' clearly shows that the definition of secession in section 2(d) of the Act is not exhaustive but purely illustrative. Thus, if any association does an act which amounts to the assertion that a part of India will not remain with it, such an act amounts to secession as defined in the Act. It is not necessary for the application of section 2(d) that there should be a positive assertion or a positive act to sponsor that a part of India will not remain in its territory, but if anybody sponsors a claim which may involve this process, it will fall within the ambit of secession as defined by section 2(d) of the Act. Despite the definitions given above, the act of cession or secession would not amount to unlawful activity unless it fulfills the conditions given in section 2(f) of the Act quoted above. The definition of unlawful activity refers to an action taken by an individual or an association by any mode or method, that is, by an act or words spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, which is intended, or

supports any claim to bring about the cession of a part of the territory of India or the secession of the part of the territory of India from the Union or which incites any individual or group of individuals to bring about the aforesaid results (cession or secession). Another essential ingredient of the "unlawful activities" is that the action must disclaim, question, disrupt or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India. To put it in a more practical fashion, the essential ingredients of unlawful activities are as follows :—

- (1) There must be an action taken by an individual or an association.
- (2) Such an action is intended or supports any claim to bring about cession of a part of the territory of India or to bring about secession of a part of the territory of India from the Union or which incites any individual or groups of individuals to bring about cession secession.
- (3) The action, falls within the ambit of unlawful activity even if it is based on any ground whatsoever, that is to say no justification can be pleaded if the conditions mentioned in section 2(f) are fulfilled.
- (4) That the action disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India.

Unless the aforesaid conditions and ingredients are fulfilled, the action of an individual or an association cannot be held to be an unlawful activity within the meaning of of section 2(f) of the Act. Section 2(g) further goes on to define an unlawful association so as to include any association which has for its object any lawful activity or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or whose members undertake such activity."*****

"Section 4, sub-clause (1) clearly empowers the Tribunal to decide the question as to whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. The word "sufficient cause" has not been defined in the Act but it is a term of well known legal significance and its denitions need not detain us any longer. But the important point to note is the context in which the words "sufficient cause" have been used. But before going to the context, it is necessary to examine sub-section (3) which provides the mode in which an inquiry into the matter has to be held by the Tribunal and the grounds on which the decision has to be given. The words 'it shall decide whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful' clearly denote that the jurisdiction of the Tribunal to examine the validity of the notification is confined to the object and the provisions of the Act itself. Thus the word sufficient cause in section 4 sub-clause (1) and (3) would have to be determined with reference to the definitions given in section 2(b),(c), (d), (f) and (g) of the Act as discussed above. In other words, what the statute requires is that the Tribunal should find out whether or not there are cogent reasons or sufficient materials to prove that the individual or association sought to be banned under the impugned notification falls within the definition of unlawful activity as given in section 2(f) of the Act. It is not within the province of the Tribunal to take circumstances outside the ambit of the Act in order to find out as to whether or not there are sufficient reasons to confirm the notification. In other words, once the Tribunal accepts the evidence produced by the Government to prove that the individual or association banned falls within the mischief of section 2 of the Act, then there is sufficient cause for confirming the notification. If the Tribunal finds that there is no reliable evidence to prove that the association or individual falls within the definitions given in section 2 of the Act, then there is no sufficient cause and the notification has to be cancelled. *****

The word "sufficient cause" therefore merely indicates that the Tribunal has to see as to whether or not there are sufficient materials to prove that the association was guilty of an unlawful activity so as to be banned by the Government under section 3 of the Act. If this was not the intention of the Parliament then section 3 would have been rendered nugatory and the object of the Act to provide for a preventive statute could not be carried out."

With respect I am in complete agreement with the learned Tribunal regarding the interpretation given to the above provisions.

10. Issues No. 1 and 2 are inter-connected and will be taken up together.

As observed earlier, in order to prove its case the Government have examined three witnesses namely, P.W.1, P.W. 2 and P.W. 3, and have produced a large number of documents which will be discussed hereinafter.

11. Mr. B. K. Das, the learned counsel for the Government, divides the documents exhibited in the proceeding into two part: namely, (A)—Ext. 22, Ext. 23, Ext. 24, Ext. 24(1), Ext. 25, Ext. 25(1), Ext. 26, Ext. 27, Ext. 36 and Ext. 52. These exhibits show the contact of the N.N.C. and other bodies with foreign powers in collecting money and military training for the purpose of jeopardising the integrity of India.

(B)—The other exhibits relate to the violent incidents perpetrated by the N.N.C. and other bodies within the territory of India to achieve their objective of creating an independent Nagaland State. These exhibits will be discussed while analysing the evidence of the witnesses in proper places.

P.W. 1 Shri S. Loveraj one of the Directors to the Government of India, Ministry of Home Affairs, was examined on behalf of the Government. He has proved a number of documents and these were proved from the files and records of the Home Ministry. He proved the following documents.

Ext. 1 dated 12.9.63 which is a directive issued by the Government of India to the Chief Secretaries of all States and Union Territories to submit Fortnightly reports on political and law and order situation in the States. He states that in pursuance to the directive issued under Ext. 1, the situation reports Exts. 2 to 9 were furnished by the Nagaland Government to the Home Ministry, Government of India.

Ext. 2 is dated 12.2.74 which relates to a case of explosion, It also refers to the incident of hostile opening fire where the Indian troops returned fire and hostiles escaped towards Teseru.

Ext. 3 dated 13-2-74 refers to a firing incident 400 yards west of Chechama.

Ext. 4 dated 4-7-74 is regarding loot and arson at Chazuba where the vehicle of the S. D. O., P. W. D., Chazuma was stopped by two armed hostiles at 1545 hours and he was robbed of Rs. 600 and five wrist watches belonging to the passengers were also taken away.

Ext 5 dated 10-8-74 gives a list of forcible collection of tax and ration by Naga Army and other underground Nagas.

Ext 6 dated 26-6-74 refers to kidnapping of one Litumup-tan aged 15 years by Lt. Meyisusu and that kidnapped person is belived to have been killed. It also refers to the forcible collection of rupees 500 for the release of a kidnapped person at Purabami. There is also mention in this exhibit that the undergrounds orderd some youths of village Yongyimsen to Join Naga Army and on their refusal, under grounds decided to kidnap them.

Ext. 7 refers to some of the incidents of collection of tax and ration during the month of March, 1974, by the Naga Army and other underground Nagas.

Ext. 8 dated 3/4th March, 1974 refers to some violent incidents occurred in the month of February, 1974, where sabotage work in Kohima, Tuensang, Manipur and also of collection of tax, ration and fines were mentioned. In that exhibit there is also mention that a group of 200 Naga Hostiles under S. S. Gen. Povizo crossed over into Burmah during December, 1973 on their way to China. It also mentions another group of 90 under the leadership of Th. Muivihwas also reported to have crossed over in May 1973. In this exhibit there is also mention in details of the casualties during the period 1st to 18th February, 1974.

	Nagaland		Manipur joint
(a) Own.			
(i) Killed	18	2	20(4 civilians Killed not included)
(ii) Wounded	21	19	31 (2 civilians wounded not included)
(b) Hostiles			
(i) Captured	30	3	02
(ii) Surrendered	29	—	29
(iii) Suspects apprehended	4	3	44

by the security Forces and a list of recoveries of arms and ammunition

Ext. 9 dated 8/9-1-74 refers to forcible collection of ration and tax by the Naga Army and undergrounds during December 29, 1973 to January 21, 1974.

Ext. 10 is a Fortnightly confidential report sent by the Chief Secretary to the Government of Nagaland to the Secretary, Government of India, Home Ministry. It refers to the period of second half of May 1974. It refers to collection of 8 Kgs. of rice and one fowl from the village of Zeliang area by the undergrounds. It mentions also of joining two boys in the Naga underground set up from Tophema village. It mentions of B.S.F. personnel being shot dead by the undergrounds near Nachama village in Kohima district. It mentions the kidnapping of one Molpi of Tokubama village by the undergrounds and shot dead on 23rd May, 1974 near Kerkrima village in Phek district. There is also mention of kidnapping of four V. Gs of Thonoknyu village in Tuensang district by the undergrounds from Makwere village (Burma side) when they went to the village without arms for purchase of some articles. It also mentions about two boys being kidnapped on May 26.

Ext. 11 is the Fortnightly confidential report for the first half of June, 1974. From this exhibit it is found that one Assam Rifle personnel was shot dead by the undergrounds three kilometers away from Lazami village in Kohima district. It also mentions about one security force personnel being killed by the undergrounds. It mentions also of arrest of seven persons by the civil authorities with the help of NAP/CRP/SF for their unlawful activities from Mokokchung and Phek districts.

Ext. 12 is the Fortnightly Confidential report for Nagaland for the first half of July, 1974. From this exhibit it appears that on July 12, helicopter in which the General Officer Commanding, 8 Mountain Division was flying, was fired upon by undergrounds near Phesachaduma and Theprezumi villages in Phek District. As a result the General Officer Commanding received bullet injury. Curfew was imposed on ten villages in Phek District and eleven villages in and around Kohima town for 72 hours. On July 13, a Security Forces patrol was fired upon by undergrounds near Rukroma villages in Phek District. As a result the General Officer was killed. On July 4, two armed personnels suspected to be undergrounds stopped the vehicle of the S.D.O. Public Works Department and robbed him of Rs. 600 and five wrist watches of the occupants of the vehicle. On July 7, one work charged Overseer of Police Project while returning from Chumukedima with staff pay was robbed by some miscreants. On July 8, a gang of ten armed personnel clad in Olive Green uniform came to the new Police Reserve site near Phasama in Kohima District and forcibly took away an amount of Rs. 150 from the labourers. On the night of July 12, some miscreants entered into the office room of the Government High School at Phek and took away two typewriters. This exhibit also shows that the civil authorities with the help of Police, C.R.P., Security Forces intensified patrolling to check the unlawful activities, and as a result of such action some arms and ammunitions were recovered from the underground hostiles and some of the suspected undergrounds were apprehended.

Ext. 13 is a Fortnightly Confidential report of Nagaland for the first half of August, 1974. From this exhibit it appears that in last week of July, 1974, a gang of undergrounds visited Japu village in Mokokchung District and recruited two boys viz. Tongapanglepden and Lanuwati of the same village. In this connection five C.Bs/Barricks were

arrested. During the first week of August one Neisetso of Merema village in Kohima District was reported to have joined the underground set-up. On August 8, one Pukronyi of Phogumit village in Phek district was kidnapped by undergrounds from Zunhehoto-kohima road. On August 11, women namely Sasue Sakhesang and Nsillo Chakhesang were reported to have been kidnapped by the undergrounds. During the first half of August, 1974, 12 persons from the village of Japukong range in Mokokchung district were kidnapped by the undergrounds. On August 14, a villager of Tsapomi village was kidnapped by undergrounds. On August 10 the civil authorities arrested one Takumukden Ao of Mopongchukit village in Mokokchung district while collecting tax and ration for the undergrounds. On August 2, some miscreants entered into the office room of the Headmaster of Ongpangkong High School in Mokokchung, District and took away one Iron Chest containing Rs. 2000. On August 18, one Mezangol Angami of Khuzama village was murdered by one Zepropal Angami of the same village. From this exhibit it appears that the civil authorities with the help of NAP/CRPF/SF/BSF intensified patrolling and searching in the villages to curb unlawful activities during the period as a result of which some arms and ammunitions were recovered from the possession of the undergrounds. On August 5, one SS Maj. Pukroy of Jakhama village in Kohima District surrendered to the Deputy Commissioner, Kohima with one Hand Grenade. On August 9, on receipt of secret information about the presence of SS Maj. Velhinyi in Chupuzumi village, a patrol of CRPF was sent to apprehend him. The underground was armed with sten gun and a pistol. He opened fire at one CRPF personnel and managed to escape into the jungle leaving behind his sten gun with two magazines. As a result of the firing the CRPF personnel was killed. On August 10, a patrol of Assam Rifles while searching Changrongia Imchen village in Mokokchung District notice one person trying to escape through the roof of a house. The patrol opened fire to stop him and as a result he was killed. The killed person was later identified as Marchiba of the same village. On August 13, a patrol of B.S.F. raided one underground camp near Chomequma village in Kohima District and an exchange of fire took place between the patrol and the undergrounds and as a result one head constable of the B.S.F. patrol was killed. The undergrounds managed to escape into the jungle. During the period of this report 37 persons were arrested by civil authorities for their unlawful activities and 43 persons surrendered to civil authorities without arms.

Ext. 16 is the "Yehzabo" of Nagaland which is the Constitution of the Federal Government of Nagaland. This exhibit was also produced and proved before the Tribunal constituted for adjudicating the notification under Sub-section (1) of Section 3 of the Act published on 1-9-72, by which the N.N.C. and other bodies were declared unlawful associations. In the earlier proceeding the learned Tribunal considered the provisions of this Yehzabo in greater detail. The Preamble to this exhibit "Yehzabo" (Constitution) reads as follows :

"We the people of Nagaland, solemnly acknowledging that the sovereignty over this earth and the entire universe belongs to Almighty God alone, and the authority of the people to be exercised in the territory is a sacred trust from God, who sustained our fore-fathers, the national workers and our people through the years of trial, and having our attachment to the trust of popular sovereignty as declared on March 22, 1956, and the Articles contained in the Provisional Yehzabo of 1962, to establish national institutions based on the common ideas of Democracy, Equality, Justice, Liberty and Fraternity among the people composing it, do hereby adopt in our National Assembly the (amended) Yehzabo of Nagaland this Twenty fifth day of July, in the year of our Lord Nineteen hundred and sixty eight."

12. Some of the relevant Articles of the so-called Yehzabo (Constitution) of the rebel Nagas are quoted below :

"Article 1.—The territory of Nagaland shall comprise all the territories inhabited by the indigenous Naga Tribes and such other territories as Tatar Hohi may, by law, admit on such terms and conditions as it deems fit.

Article 8—The name of the National Government shall continue to be called "THE FEDERAL GOVERNMENT OF NAGALAND."

Article 9—There shall be but one citizenship throughout Nagaland, that is to say, there shall be no citizenship of the Unit as distinct from that of the Union.

Article 19—The Executive power of the Federal Government of Nagaland shall be vested in the President and shall be exercised by him with the Council of Kiloners in accordance with the provisions of this Yehzabo and

Article 30(a)—The President shall be the Supreme Commander of Armed Forces of Nagaland, and

(b) In exercise of his powers as Supreme Commander, the President shall have power to issue directives for disposition of Armed Forces for planning and execution of military campaigns, to deal with emergencies like foreign invasion and any matter appertaining to the conduct of war.

Article 43—There shall be a Council of Kiloners, with equal status, to aid and advise the President in exercise of his powers and functions.

Article 51—There shall be a Federal Parliament consisting of two Houses known as Kimhao (Upper House) and Tatar Hoho (Assembly of Representatives).

Article 89—There shall be a Federal Supreme Court of Nagaland consisting of a Chief Justice and four other Judges.

Article 101—There shall be a Regional Council for each Region consisting of members elected by Sub-Regional Councils.

Article 107—There shall be an Executive Head in a Region called Midan Peyu.

Article 116—There shall be a Sub-Regional Council in every Sub-Region and a Sub-Regional Council be composed of the representatives of village councils.

Article 117—The Village Council shall, in the Sub-Regional Council, be represented by its Runa Peyu or any person authorised in this behalf.

Article 118(a)—The Sub-Regional Council shall have the local administrative powers in the area under the direction of the Regional Council, and the administrative power for the Sub-Regional Unit shall be exercised by the Raju Peyu as its Administrative Head.

Article 121—There shall be a Regional Court for each Region.

Article 129—There shall be a Sub-Regional Court for each Sub-Region and the number of Judges shall be determined by the Regional Council.

Article 133—The Village Court shall be the lowest judicial Court in Nagaland, and the administration of justice shall be regulated according to their customs, traditions and usages.

Article 137—The Federal Government of Nagaland shall maintain a standing National Army.

Article 138—The organisation for defence shall be regulated by the Tatar Hoho in consideration of the situation prevalent in the Country.

Article 139—The Federal Government of Nagaland shall maintain Diplomatic Relations with all Nations.

Article 141—Christianity and Naga Religion are recognised Religions in Nagaland.

Article 143—The Naga National Council shall be the only recognised political institution in Nagaland."

13. Page 22 of the exhibit refers to the population of the Federal Government of Nagaland specifying the tribes

in that territory. At serial No. 6 of this list Konyak tribe has been mentioned. This tribe lives in Arunachal Pradesh in Tirap district and some are spread over in Burma. At serial No. 13 Shepumaramth tribe is mentioned. This tribe also lives in some parts of the State of Manipur. At serial No. 14 Tankhul tribe is mentioned. This tribe also lives in the adjoining State of Manipur. At serial No. 17 Zaliangroung tribe is mentioned. This tribe also lives in the adjoining State of Manipur and spills over in Assam in North Cachar Hills District. This exhibit clearly illustrates the aims, objectives and ideology of the N.N.C. and other bodies under it. It shows that the N.N.C. and other bodies have for their objective to set up a Government of their own by secession of the territory of the Union. This exhibit also shows that it has provided for all the trappings of the civil and military administration.

Ext. 17 dated 16th October, 1972 is a photostat copy of the directive issued by the Naga Army signed by Zashei Huire, President, Federal Government of Nagaland. This document was addressed to the Commander-in-Chief of the Naga Army by the President and from this exhibit it appears that the President exerts the Naga Army about the duty and functions to preserve peace in his own land in strict observance of laws and practices of the land, speaks of India as an aggressor in causing to Nagaland much grief and sorrows. It also speaks about declaring Naga National Council and other bodies under it, unlawful associations according to the provisions of the Act. It further says "Be it known therefore that in our homeland we are being hunted and we are being killed by the Government of India. That our persistent effort to bring peace in the land was spurned and repulsed by the Government of India. That mischief and wickedness prevail in the camps of India and no truthful composition have any space in the mind and in the activities of the Government of India in Nagaland." This document further runs as follows : "It is, therefore, with powers and provision laid down in Articles 27 and 30 of the Yehzabo (Constitution of Nagaland), the present Directive is hereby issued to the Naga Army.

(a) That all casual leave and long term leave will not be extended to the Naga Army personnel from 1st November, 1972 unless he is incapacitated by illness or other serious reasons ;

(b) That all resignation letters submitted to the authority by officers and other ranks will not be entertained for consideration until further notice on this specific subject.

(c) All Naga Army stations are directed to keep constant alert against enemy attacks.

That the honour of the people and the defence of the homeland shall be maintained at all costs."

Ext. 18 dated 2-7-1973 is a photostat copy of the Extraordinary Ahza issued by the Lt. Gen. Vivalie Metha, Commander-in-Chief, Naga Army. This exhibit gives a direction to the Army to chalk out a fresh lighting programme and resume fightings at any suitable place with effect from 1st August, 1973. The duration of the command period is up to the end of September, 1973. It mentions some of the categories of duties as follows :

1. Attack enemy post or ambush.
2. Obstructed the enemy communications.
3. Damaged any properties of the enemy.

Failure to comply with this Ahza shall be treated as a case of negligence and the Unit Commander or Officer shall be penalised per rules."

Ext. 19 dated 16th November, 1973, is issued by the Killo Kiloner (Home Minister) Biseto Medon Keyho, by which the election in Nagaland under the Indian sponsorship was declared illegal. The relevant portion runs as follows :

"Any election in the Naga home-land under Indian sponsorship is crystal-clear repeated attempts of India to destroy Naga Nation. Hence, any citizen

participating in the Indian sponsored election..... constitutes outright high treason, pardonable on no ground. Citizens of Nagaland, you are, therefore, warned hereby in the law of the Nation that under no circumstances Nagaland brooks anti-national activities.

All the Regional authorities—Midan Peyus, Regional Presidents, Brigade Commanders and Battalion Commanders are hereby ordered to promptly execute the Ahza."

Ext. 20 gives details of violent incidents in Nagaland and Manipur from 1972 to August, 1974. It also gives the figures of kidnapping in Nagaland and Manipur and persons killed and injured in Nagaland and Manipur for 1972, 1973 and up to 31st August, 1974. It also gives the figures of forcible recruitment in Nagaland and Manipur for the same period and forcible collection of tax in Nagaland and Manipur during that period. It records violent incidents at 64 in Nagaland and in 14 in Manipur. It also records the cases of kidnapping in Nagaland 64 and in Manipur—8. From this exhibit it appears that the persons killed and injured by the Naga undergrounds in Nagaland and Manipur in 1972, 3 Security Forces were killed, 4 civilians killed in Nagaland, in Manipur 1 security force killed and 7 civilians killed. In 1973, in Nagaland 12 Security forces killed, 28 injured, 19 civilians killed and 42 civilians injured, and in Manipur 21 Security forces and 6 civilians were killed. In 1974 upto 31st August in Nagaland 42 Security forces killed, 28 injured and 18 civilians killed and 4 injured; in Manipur 3 Security forces killed, 4 injured and 2 civilians killed and 2 civilians injured. It also records forcible recruitment in Nagaland and in Manipur as follows :

Year	Nagaland	Manipur
1972	101	134
1973	116	55
1974		
(Upto 31—8—74)	424	67

It also records the forcible collection in Nagaland and Manipur as follows :

Year	Nagaland Rupees	Manipur Rupees
1972	1,89,998	1,45,624
1973	3,74,705	1,48,025
1974		
(Upto 31—8—74)	3,51,374	48,140

Ext. 21 mentions 145 violent incidents during the period 1st September, 1972 to August 31, 1974. It gives some details of those incidents. From this exhibit it appears that there are so many violent incidents perpetrated by the Naga undergrounds in killing, injuring and looting the Security Forces and civil population. In this exhibit also there is an enclosure showing the statement of violent incidents, from September 1, 1972 to August 31, 1974. Regarding the incidents in Nagaland it records 145 incidents and regarding violent incidents during that period in Manipur 38 are recorded.

Ext. 22 dated China, 14th November, 1972, is a photostat copy of a document issued by T. Pushu Venu, Special Representative, Federal Government of Nagaland, to the Free Kachinland. This document lays down eight principles in China's Aid to Foreign Countries in 1972, and those eight principles are detailed in this document.

Ext. 28 dated China, 13th November, 1972 is addressed to the Commander-in-Chief, Federal Government of Nagaland Army, and all the GOCs, Federal Government of Nagaland by T. Pushu Venu, Special Representative, Federal Government of Nagaland to the Free Kachinland. It refers to the activities of the Naga Army and particularly those going to China, regarding their discipline.

Ext. 24 dated Oking, 1st June, 1973, addressed to the President, Federal Government of Nagaland by Col. Vedai Moire, Commander, Alee Command N. A., Federal Government of Nagaland with copies to the Commander-in-Chief,

N. A., Federal Government of Nagaland and the Adjutant General, N. A. Federal Government of Nagaland, with a list of names of the Naga Army who were on Alee Command during 1972-73. This list is Ext. 24(1).

Ext. 25 dated 9th June, 1973, is a photostat copy of the letter issued by Col. Vedai Moire, Naga Army, Federal Government of Nagaland addressed to the President, Federal Government of Nagaland. The subject of the letter is of furnishing a list of articles given by the Government of People's Republic of China to the Federal Government of Nagaland. The list enclosed therewith is a photostat copy which is marked Ex. 25(1). The list contains arms including Naga National Flag and articles exclusively used for demolition work. Items 59, 60 and 64 of the list refer to Rocket Cleaning Rod, Rocket Driving Charge and Rocket firing pin. Items 9, 10 11 and 12 of the list are used for destruction of bridges and railway lines, according to the deposition of this witness.

Ext. 26 dated 23rd June, 1973, is a copy of the letter written by Maj. K. Neilie, 2nd Bde. W/C, Naga Army addressed to the Commander-in-Chief of Federal Government of Nagaland, congratulating the Alee Command party, and says that all of the them rejoice that Alee Command returned safely to their homeland through the divine of God.

Ext. 27 dated 1st July, 1973, is a photostat copy of a letter written by Maj. Gen. P. D. Soho, GOC, Eastern Command, Naga Army, addressed to the Adjutant General, N. A., Federal Government of Nagaland on the subject "Long term policy and plans," of the Naga Army. It says about the recognition of the Federal Government of Nagaland by China and other Christian countries. It mentions the desire of the Nagas to join a defence pact with China. It mentions "Once such pact is signed cowardly India will pull out its forces much beyond Dimapur and Mariani." It also mentions that the Federal Government of Nagaland is establishing further contacts for material aid from China for weapons capable of shooting down air-craft or destroying tanks."

Ext. 28 dated 2-6-1973 is a photostat copy of Chapleo Receipt issued by Isak Chishi Swu, Chapleo Kilonser, Federal Government of Nagaland. It refers to the money received from Col. Vedai Moire from Alee Command in two items, namely, one for Rs. 86,730 and the other for Kts. 22,811.

Ext. 29 dated 9th May, 1973 is a photostat copy of the letter written by Zashei Huire, President, Federal Government of Nagaland to Dr. Curt Waldheim, Secretary General, United Nations Organisation, New York City. It records a complaint against India and says India is determined to deploy force in her renewed attempt to take Nagaland. It seeks intervention of the United Nations Organisation and appeals that an International Commission come to Nagaland and study the existing military situation. Copies of this communication were sent to United Kingdom, China, United States, Union of Soviet Socialist Republic, Japan, France, Pakistan, Belgium and Albania.

Ext. 30 dated 28th September, 1973, is a photostat copy of a letter written by Zashei Huire addressed to the Vice President, Naga National Council, Urra Ao Region. It says from 1947 to 1956 and from 1956 to 1967 they had the Ino-Naga war-fare that made history. It also says that with bullets and money bag politics, India had succeeded and they have a full dose of Naga problems everywhere. It also says that they have the second front to face is the activities of spies and reporters in the villages. It also refers to the general election as enemy election. It further mentions launching of counter measures against the proposed election. It says that Zashei Huire has declared every organisation other than the Naga National Council as illegal organisation in Nagaland and therefore expects strong measures that would deal with the political situation in Nagaland.

Ext. 31 dated 3rd May, 1973, is a photostat copy of a letter written by Maj. Gen. M. Assu Angami, G.O.C., Western Command, Naga Army, addressed to the Commander-in-Chief Naga Army. The subject of this letter is Fighting Report, on 29th April, 1973, QM. Maj. Krutsu's party returned from command to Headquarters, met the Indian operation party

and L/Corporal Medolhou returned fire to enemies and killed one man of the Indian army.

Ext. 32 dated 5th May, 1973 is a photostat copy of a letter written by Maj. Gen. M. Assa Angami, G.O.C., Western Command, Naga Army addressed to the Commander-in-Chief, Naga Army, and the subject of this letter was Combined Fighting Report, which mentions of the fighting that took place between the Naga army and the Indian State Force (NAF), in which Naga army killed three Indian force personnel and seized arms and ammunitions and one Phillip radio.

The witness is producing four more documents which, according to the witness, came to the Home Ministry in the routine course of reporting.

The first document is Ext. 33 dated Urrs, 3-4-74, which is a copy of a letter from Midan Peyu, Angami Region, Federal Government of Nagaland addressed to Chaplee Kilonser, Federal Government of Nagaland, and the subject of the letter is Annual report of Federal house tax. This exhibit contains a list of collection of house tax in Nagaland and the list is marked Ext. 33(1).

Ext. 34 dated May 3, 1974 is a copy of a letter from Biseto Medom Keyho, Killo Kilonser (Home Minister), Federal Government of Nagaland addressed to Mr. A. Z. Phizo, President Naga National Council and the Representative Abroad of the Federal Government of Nagaland. It forwards copies of decision taken by the Cabinet on the question of Naga prisoners of war. Along with this document a copy of the decision taken by the Cabinet of the Naga Federal Government, was enclosed which is marked Ext. 34(1). The Cabinet decisions recorded in Ext. 34(1) regarding the Naga prisoners of war reads:—

"It has come to the notice of the Federal Government of Nagaland that the prisoners of war, now awaiting trial in Shillong, Meghalaya State, have so far refused to receive notices served on them by the Indian Special Court which is to try them. The ground for their refusal to appear before the said Court is said to be that they would not secure the ends of justice unless they are defended by International lawyers. The fear expressed in this connection by the Naga prisoners of war is fully shared by the Federal Government of Nagaland, and therefore, is of the strong opinion that the only way to handle, this ticklish issue to engage lawyers from England.

However, in view of the fact that the expense to be incurred on this count are likely to be heavy, and in view of the critical financial position of the Federal Government, the Cabinet in a review of the whole situation, has taken a decision that Mr. A. Z. Phizo, President of the Naga National Council, and representative abroad of the Federal Government of Nagaland, be urged to take such immediate steps as:—

- (a) to explore the possibility of engaging lawyers from England to defend the Naga prisoners of war who have been languishing in Indian Jails;
- (b) and to appeal to the Minority Group, the Anti-Slavery Society, London, and any individual for help which the Federal Government shall gratefully acknowledge."

Ext. 35 dated 30th July, 1974, is a copy of a letter from Lt. Gen. Vivalie Metha, Commander-in-Chief, Naga Army, addressed to the General Officer Commanding, Eastern Command, Naga Army. The subject of the letter is congratulations which mentions courageous reprisal of the Naga army who had shot down the helicopter which was carrying the enemy G.O.C. which means the Indian G.O.C. who escaped only by fate. It also says that the Commander of the Naga army is proud of that.

The 4th document is a letter from the President, Federal Government of Nagaland addressed to the Prime Minister, People's Republic of China. But as this letter is undated, therefore, it is not possible to ascertain whether this letter was in possession of the Government at the time of issue of the notification under Section 3(1) of the Act. Hence the Tribunal feels that this letter cannot be considered.

Ex. 37 dated 26th November, 1974 is a copy of acknowledgement receipt given by Isak Chishi Swu recording the receipt of a sum of Kts. 7,157 from Mr. Thepuske Venu brought under the head of National income from the Foreign Aid from China on May 3, 1974. The witness has produced and proved the above documents from the record of the Central Government. Therefore, there is no reason to doubt the genuineness of the documents which are proved by the witness. Moreover, some of these documents produced and proved by P.W.1 are proved in original by P.W.2 who recovered and captured those documents from the possession of the undergrounds.

14. P.W.2 Diwan Singh who is N/Subedar, 10 Assam Rifles at Mokokchung was examined as a witness by the Central Government. He states that he has been working in Nagaland for the last 18 years. According to the witness in Nagaland there are two parties, one the Naga National Organisation working in favour of the Indian Union and the other is Naga Federal Government working against India. Therefore, according to the witness, they are posted in Nagaland for the purpose of controlling them who are working against India. In 1973 the witness was posted at the Military Outpost named Nangemeton. At that time he along with others captured one person belonging to the underground organisation. That captured person was brought to the Outpost. On interrogation, the captured person agreed to disclose a hide-out of the undergrounds. Accordingly, he along with a platoon consisting of 20 sepoy, raided the hide-out sometime in 1973. There was an exchange of fire between the undergrounds and the witness's men and the undergrounds fled away. They could not find anything in the hide-out, but outside the camp in the jungle a steel box was recovered which contained certain documents. This witness recovered the documents which are exhibited as Ext. 38, Ext. 39, Ext. 40, Ext. 41, Ext. 42, Ext. 43(1), Ext. 44, Ext. 44(1), Ext. 45, Ext. 46, Ext. 47, Ext. 48, Ext. 49, Ext. 50 and Ext. 51. All these documents were seized by the witness. These documents are the originals of Ext. 17, Ext. 18, Ext. 19, Ext. 22, Ext. 23, Ext. 24, Ext. 24(1) Ext. 25, Ext. 25(1), Ext. 26, Ext. 27, Ext. 28, Ext. 29, Ext. 30, Ext. 31 and Ext. 32 respectively, regarding which a full discussion has been made in analysing the evidence of P.W.1.

15. P.W. 3 Sri Hesso Mao is a Deputy Superintendent of Police, Special Branch in Nagaland. He has been working in the Special Branch since 1967. He had a special training in this line in 1966. The duty of the witness is to collect intelligence in connection with the anti-national activities in the State of Nagaland. Their main duty is concentrated in the Naga underground activities. He was born and brought up in Mao area. Although that Mao area falls in Manipur, it is predominantly inhabited by Naga people where there is anti-national elements and undergrounds. That is how he comes to know personally most of the workers and leaders. In order to collect information, according to the witness, there are many agents working under him in the Special Branch. Some of the documents which were collected by the witness's agents were produced before the Tribunal and the following are those documents produced and proved by the witness.

Ext. 52 dated 7-4-73 is a document on the subject of Annual Budget for the year 1973-74 signed by Isak Chishi Swu, Chaplee Kilonser, Federal Government of Nagaland, addressed to the Tatar (Kuhovi Jimomi), Federal Government of Nagaland. Ext. 52 (1) is the signature of Isak Chishi Swu, Chaplee Kilonser, Federal Government of Nagaland, which is identified by the witness. Ext. 52 (2) is the budget estimate enclosed. Apart from measures for raising revenue from various sources, in item No. 6 of Ext. 52(2) there is a provision for taking Raka one and half millions loan or aid from Foreign countries. In summing up the source of national income under different heads for the year 1973-74, the following figures are shown in Ext. 52(2):

1. House Tax	Raka	147,000/-
2. Loan Fund	Raka	75,000/-
3. Compulsory Loan	Raka	100,000/-
4. Motor Vehicle Tax	Raka	48,000/-
5. Court	Raka	67,000/-
6. Foreign Loan and	Raka	1,500,000/-
7. Federal subscription	Raka	1,809,375/-
Total	Raka	3,746,375/-

Ext. 53 dated 10-5-73 is a copy of a letter addressed to the President, Federal Government of Nagaland by L. M. Shobe Swu, Midan Peyu, Sema Region on the subject of Annual report. Ext. 53(1) is the enclosed list regarding annual report. Ext. 53(2) is the signature of L. M. Swu, Midan Peyu, Sema Region which the witness identifies.

Ext. 54 dated 21-6-72 which is a circular issued by M. Jamir, Kilonser, Information and publicity, Federal Government of Nagaland on the subject 'Indo Naga warfare is not a law and order issue.' Ext. 54(1) is the signature of M. Jamir, which the witness knows and identifies.

Ext. 55 dated 6-2-74 is the situation report submitted by the Commandant 4th Btn. Naga Armed Police. In this document there is mention of taking of goods by undergrounds and killing of 7 N.A.P. personnel between Wokha and Kohima. It relates to the incidents which occurred on 6-2-74. Ext. 55(1) is the signature of the Commandant Co. Nihar Singh which the witness knows.

Ext. 56 dated 14-2-74 is a situation report received from the Superintendent of Police, Mokokchung, informing the Chief Secretary/Commissioner on the subject of killing the Deputy Commissioner of Zunheboto, Mr. K. K. Gupta and Mr. Sailo Lushai, E.A.C. and Lann Ao, driver Ext. 56 (1) is the signature of the Superintendent of Police, Mokokchung.

Ext. 57 dated 28-7-74 is a report from the Officer-in-Charge, Kohima regarding the killing of 2 civilian population at Khonoma village. Ext. 57(1) is the signature of the officer-in-charge, Kohima which the witness knows.

Ext. 58 dated 27-7-74 is a situation report from the Deputy Commissioner, Kohima regarding the killing of 11 N.A.P. personnel at Chishilimi village on 26-7-74 Ext. 58(1) is the signature of Mr. L. L. Yaden, Deputy Commissioner, Kohima which the witness knows and identifies.

16. On a careful consideration, therefore, of the evidence, both documentary and oral, adduced by the Government, it is proved beyond doubt that the Naga National Council and other bodies under it have for their objective to form an independent State by secession of a territory of India from the Union and in furtherance of that objective, as found from the evidence, they have not only framed their Yehzabo (Constitution) but have engaged the Naga Army and other bodies to perpetrate violent activities, killing and harassing army and civil population. They have also tried to achieve their objective in collaboration with foreign countries. In my opinion, such activities fall within the mischief of Section 2(d) of the Act which are intended to support or support the claim to bring about secession of a part of the territory of India from the Union and for the purpose of secession the Naga National Council has incited the other bodies under it to achieve that objective. These activities have the effect of disclaiming, questioning, disrupting or intending to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India. So, such activities come within the ambit of Section 2(f) of the Act. As the Naga National Council and the other bodies under it are engaged in unlawful activities within the meaning of Section 2(f), therefore, they become unlawful associations within the definition of Section 2(g) of the Act. I find that there is sufficient cause for declaring the Naga National Council and other bodies under it, unlawful associations by a notification under Section 3(1) of the Act.

17. For the reasons stated above, issues No. 1 and 2 are decided in favour of the Government and the declaration that the Naga National Council, Federal Government of Nagaland, Naga Army, Kimbao (Upper House) and Tatar Hoho (Assembly of Representatives), Federal Supreme Court and other bodies under it are unlawful associations made under the notification No. S.O. 519(E) dated 1st September, 1974, issued by the Central Government and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section-3 Sub-section (ii) is hereby confirmed and the reference is accepted.

18. Let the judgment be sent to the Union Home Ministry for publication in the Government Gazette. Let also the exhibits of the case be sent to the Union Home Ministry for safe custody.

D. PATHAK, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal.

[No III-14015/43/74-NE-I]

का० प्रा० 1139.—यत्तः भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 519 (ई) तारीख 1 सितम्बर, 1974 में अन्तर्विष्ट मामलों के न्यायनिर्णय हेतु गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री डी० पाठक के अधीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 547 (ई) तारीख 16 सितम्बर, 1974 द्वारा गठित "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

और यत्तः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिकरण का अन्वयित बना रहना अनावश्यक है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि पूर्वोक्त अधिकरण इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में न रहेगी।

[सं० 3-14015/43/74-एन०ई०-2]

एस० के० मण्डी, अवर सचिव

S.O. 1139.—Whereas the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice D. Pathak, Judge of the Gauhati High Court, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 547(E) dated the 16th September, 1974, to adjudicate upon the matter contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 519(E), dated the 1st September, 1974 has completed its work;

And whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the said Tribunal is unnecessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that the aforesaid Tribunal shall cease to exist with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. III-14015/43/74-NE. II]

S. K. MAGON, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1975

आय-कर

का० प्रा० 1140.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (14) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जे० आर० जैन को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर बसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 810 (फा० सं० 404/221/74-आई टी सी सी), तारीख 1 जनवरी, 1975 के अधीन की गई कर बसूली अधिकारी के रूप में श्री जे० एस० मान की नियुक्ति उस तारीख से रद्द की जाती है जिस तारीख को श्री जे० आर० जैन कर बसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

3. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को श्री जे० आर० जैन कर बसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

[सं० 849/फा० सं० 404/35/75 आई०टी०सी०सी०]

टी० आर० अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 3rd March, 1975

INCOME TAX

S.O. 1140.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri J. R. Jain who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri J. S. Mann as Tax Recovery Officer made under Notification No. 810 (F. No. 404/221/74-ITCC) dated the 1st January, 1975 is hereby cancelled with effect from the date Shri J. R. Jain takes over as Tax Recovery Officer.

3. This notification shall come into force with effect from the date Shri J. R. Jain takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 849/F. No. 404/35/75-ITCC]

T. R. AGGARWAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1975

आयकर

का० प्रा० 1141.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है।

संस्था

वि. कर्नाटक एग्रिकल्चर फाउन्डेशन, हुब्ली, जिला धारवाड़।

यह अधिसूचना 1-4-1974 से 31-3-1976 तक प्रभावी रहेगी।

[सं० 853/का० सं० 203/6/75-आई० टी० ए० 2]

एम० के० पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th March, 1975

INCOME TAX

S.O. 1141.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

The Karnataka Agriculture Foundation, Hubli, Distt. Dharwar.

This notification will be effective from 1-4-1974 to 31-3-1976.

[No. 853/F. No. 203/6/75-I.T.A.II]

M. K. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1975

स्टाम्प

का० प्रा० 1142.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो इण्डस्ट्रियल रिकान्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा वचनपत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बो करीड़ और पचहत्तर लाख रुपये मूल्य के बंध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभावी है, छूट देती है।

[सं० 10/75-स्टाम्प/का० सं० 471/10/75-वीमाशुल्क-7]

डी० के० अचार्य, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 1975

STAMPS

S.O. 1142.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds of the value of rupees two crores and seventy-five lakhs to be issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., Calcutta, in the form of promissory notes, are chargeable under the said Act.

[No. 10/75-Stamp/F. No. 471/10/75-Cus. VII]

D. K. ACHARYA, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 5th March, 1975

S.O. 1143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (i) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 1975.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services)

Rules, 1960, in sub-rule (3) of rule 16, after the words "Housing Board" occurring in the proviso to clause (a) of sub-clause (ii), the words "nationalised banks" shall be inserted.

[No. Q. 24017/1/75 EV (B)-CPF]

S. S. L. MAHOTRA, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1973

आय-कर

का० प्रा० 1144.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, निवेदन देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (प्रपील) उनके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन आय-कर सिकलियों/वाडों और जिलों में आय-कर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर सिकल, वाडें या जिले
1	2	3
1. विशेष रेंज, कटक	(1) केन्द्रीय सिकल, कटक	(2) विशेष सिकल, कटक

1	2	3
		(3) संपदा शुल्क सर्किल, कटक
		(4) वार्ड-क (कम्पनी), कटक
		(5) वार्ड-ख (राजस्व), कटक
		(6) वार्ड-ग (राजस्व), कटक
		(7) वार्ड-क (कम्पनी), भुवनेश्वर।
2 कटक रेंज, कटक		(1) कटक सर्किल के वार्ड-क (कम्पनी) वार्ड-ख (राजस्व) और वार्ड-ग (राजस्व) को छोड़कर कटक सर्किल
		(2) रेंकानाल सर्किल
		(3) बाबासोर सर्किल
		(4) बारीपाड़ा सर्किल
		(5) कूनभर सर्किल
3. बेरहामपुर रेंज, बेरहामपुर।		(1) बेरहामपुर सर्किल
		(2) जेपूर सर्किल
		(3) भवानीपटना सर्किल
		(4) बोलनगीर सर्किल
		(5) पुरी सर्किल
		(6) वार्ड-ख (बतन) भवनेश्वर सर्किल
4 राउरकेला रेंज, राउरकेला।		(1) सम्बलपुर सर्किल
		(2) झारसुगुड़ा सर्किल
		(3) राउरकेला सर्किल

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अंतरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष संबित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल वार्ड, या जिला या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अंतरित कर दी जायेगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 21 जुलाई, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 424/फा० सं० 261/10/73-आई० टी० जे०]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 21st July, 1973

Income-Tax

S. O. 1144.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Supertax in the Income-tax Circles, wards or Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circle, Wards or Districts
1	2	3
1. Special Range, Cuttack.		(i) Central Circle, Cuttack. (ii) Special Circle, Cuttack. (iii) Estate duty Circle, Cuttack. (iv) Ward-A (Companies), Cuttack. (v) Ward-B (Revenue), ¹ Cuttack.

1	2	3
		(vi) Ward-C (Revenue), Cuttack. (vii) Ward-A (Companies), Bhubaneswar.
2. Cuttack Range, Cuttack.		(i) Cuttack Circle excluding Ward-A (Companies), Ward-B (Revenue) and Ward-C (Revenue) of Cuttack Circle. (ii) Dhenkanal Circle. (iii) Balasore Circle. (iv) Baripada Circle. (v) Keonjhar Circle.
3. Berhampur Range, Berhampur.		(i) Berhampur Circle. (ii) Jeypore Circle. (iii) Bhawanipatna Circle. (iv) Bolangir Circle. (v) Puri Circle. (vi) Ward-B (Salaries) Bhubaneswar Circle.
4. Rourkela Range, Rourkela		(i) Sambalpur Circle. (ii) Jharsuguda Circle. (iii) Rourkela Circle.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from One Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 21st July, 1973.

[No. 424(F.No. 261/10/73-ITJ]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1973

फा० प्रा० 1145.— केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का धोर उस निमित्त उसकी समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 372 (फा० सं० 261/12/72-आई टी जे), तारीख 8-6-73 को अधिकांत करते हुए, निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन आय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आय-कर या अधि-कर या घन-कर या दान-कर या व्यय-कर के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जिनके अन्तर्गत वे आय-कर सर्किल, वार्ड और जिले नहीं हैं जो अधिसूचना सं० 371 (फा० सं० 261/12/73-आई टी जे), तारीख 8-6-73 द्वारा सम्पदा-शुल्क नियंत्रक (अपील), हैदराबाद को विनिर्दिष्ट: प्रावर्तित किये गये हैं और जिनके अन्तर्गत वे अपीलें नहीं हैं जो (1) आदेश सं० 150 (फा० सं० 262/183/71-आई टी जे), तारीख 17-8-71 द्वारा सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) विजयवाड़ा रेंज से सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) गुंटुर रेंज को, (2) आदेश सं० 48 (फा० सं० 262/26/72-आई टी जे), तारीख 22-3-72 द्वारा सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) क-रेंज, हैदराबाद से और (3) आदेश सं० 145 (फा० सं० 262/48/72-आई टी जे) तारीख 11-8-72 द्वारा यथा संशोधित आदेश सं० 84 (फा० सं० 262/48/72-आई टी जे) तारीख 14-4-72 द्वारा सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) विजयवाड़ा, रेंज से सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), विशेष रेंज हैदराबाद को विनिर्दिष्ट: अन्तर्गत की गई है :

क्रम सहायक आयुक्त (अपील) की आय-कर सफिल, वाडें और जिले सं० रेंज

1	2	3
1. विशेष रेंज, हैदराबाद	(1) कम्पनी सफिल, हैदराबाद । (2) सिकन्दराबाद का कम्पनी सफिल, हैदराबाद । (3) कम्पनी सफिल (पुराना), हैदराबाद । (4) विशेष सफिल-I, हैदराबाद । (5) विशेष सफिल-II, हैदराबाद । (6) विशेष सफिल, हैदराबाद । (7) केन्द्रीय सफिल, हैदराबाद । (8) केन्द्रीय सफिल (पुराना), हैदराबाद ।	
2. क-रेंज, हैदराबाद	(1) सफिल-II, हैदराबाद । (2) सफिल-II (पुराना), हैदराबाद । (3) सफिल-III, हैदराबाद । (4) वेतन सफिल, हैदराबाद ।	
3. ख-रेंज, हैदराबाद	(1) सफिल-I, हैदराबाद । (2) परियोजना सफिल, हैदराबाद । (3) कोथागुडम । (4) बारंगल सफिल । (5) एम० पी० पी० सफिल, हैदराबाद । (6) करीमनगर । (7) खम्माम् । (8) निरमाल । (9) सांगरेड्डी ।	
4. विशाखापत्तनम रेंज, विशाखापत्तनम	(1) विशाखापत्तनम । (2) विजयानगरम् । (3) श्रीकाकुलम् । (4) अनाकापल्ली । (5) राजाहमुन्दरी । (6) सफिल-I, काकीनाडा । (7) सफिल-II, काकीनाडा । (8) बाविली (पुराना) । (9) रामचन्द्रपुरम् (पुराना) । (10) काकीनाडा (पुराना) ।	
5. विजयवाड़ा रेंज, विजय-वाड़ा	(1) विजयवाड़ा । (2) मछलीपटनम् । (3) एलुरु । (4) टानुकु । (5) पालाकोल । (6) गुदीवाड़ा । (7) अमलापुरम् ।	
6. गुन्तूर रेंज, गुन्तूर	(1) गुन्तूर । (2) नेल्ली । (3) माईका सफिल, नेल्ली । (4) टेनाली । (5) बाफला । (6) कुरनूल ।	

1 2 3

7. अनन्तपुर रेंज, अनन्तपुर
- (1) प्रोद्दूर ।
 - (2) चिस्सूर ।
 - (3) तिरुपति ।
 - (4) अयोनी ।
 - (5) नांदयाल ।
 - (6) अनन्तपुर ।
 - (7) हिन्तुपुर ।
 - (8) महबूबनगर ।
 - (9) कुड्डया ।

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सफिल, वाडें या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अंतर्गत हो गया हो वहाँ उस आय-कर सफिल, वाडें या जिले या उसके किसी भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सफिल, वाडें या जिला या उसका कोई भाग अंतर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वाडें या जिला या उसका कोई भाग अंतर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अंतर्गत कर दी जायेगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 16-8-73 से प्रभावी होगी ।

[सं० 434 फा० सं० 261/12/73-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 14th August, 1973

S.O. 1145.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in supersession of notification No. 372 (F.No. 261/12/72-ITJ) dated 8-6-73, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Asst. Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income tax or Super-tax or Wealth-tax or Gift-tax or Expenditure-tax in the Income-tax circles, wards and Districts specified in corresponding entry in column (3) thereof, excepting those that have been specifically allotted to the Appellate Controller of Estate Duty, Hyderabad by Notification No. 371 (F.No. 261/12/73-ITJ) dated 8-6-73 and the appeals specifically transferred (1) from the Appellate Asst. Commissioner of Income-tax Vijayawada Range to the Appellate Asst. Commissioner of Income tax Guntur Range, by order No. 150 (F.No. 262/183/71-ITJ) dated 17-8-1971 (2) from the Appellate Asst. Commissioner of Income-tax, A-Range, Hyderabad by order No. 48 (F.No. 262/72-ITJ) dated 22-3-1972 and (3) from the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Vijayawada Range to the Appellate Asst. Commissioner of Income-tax, Special Range, Hyderabad by order No. 84 (F.No. 262/48/72-ITJ) dated 14-4-1972 as amended by order No. 145 (F.No. 262/48/72-ITJ) dated 11-8-1972:

S. Appellate No.	Asst. Commis- sioner's Range	Income-tax Circle, Ward and District
1	2	3
1. Special Rang, Hyderabad.		1. Company Circle, Hyderabad. 2. Company Ward of Secunde- rabad Circle, Hyderabad. 3. Company Circle (Old) Hyde- rabad. 4. Special Circle-I, Hyderabad. 5. Special Circle II, Hyderabad. 6. Special Circle, Hyderabad. 7. Central Circle, Hyderabad. 8. Central Circle (Old) Hydera- bad.

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1973

1	2	3
2. A-Range, Hyderabad.	1. Circle-II, Hyderabad.	
	2. Circle-II (Old), Hyderabad	
	3. Circle-III, Hyderabad	
	4. Salary Circle, Hyderabad	
3. B-Range, Hyderabad.	1. Circle-I, Hyderabad	
	2. Project Circle, Hyderabad	
	3. Kothagudem	
	4. Warangal Circle	
	5. M.P.P. Circle' Hyderabad	
	6. Karimnagar	
	7. Khammam	
	8. Nirmal	
	9. Sangareddy	
4. Visakhapatnam Range Visakhapatnam.	1. Visakhapatnam	
	2. Vizianagaram	
	3. Srikakulam	
	4. Anakapally	
	5. Rajahmundry	
	6. Circle-I, Kakinada	
	7. Circle-II, Kakinada	
	8. Bobbili (Old)	
	9. Ramachandrapuram (Old)	
	10. Kakinada (Old)	
5. Vijayawada Range, Vijayawada.	1. Vijayawada.	
	2. Machilipatnam.	
	3. Eluru	
	4. Tanuku	
	5. Palakolo	
	6. Gudivada	
	7. Amalapuram	
6. Guntur Range, Guntur.	1. Guntur	
	2. Nellore	
	3. Mica Circle, Nellore.	
	4. Tenali	
	5. Bapatla	
	6. Kurnool	
7. Anantapur Range, Anantapur.	1. Proddatur	
	2. Chittoor	
	3. Tirupathi	
	4. Adoni.	
	5. Nandyal.	
	6. Anantapur.	
	7. Hindupur	
	8. Mahaboobnagar	
	9. Cuddapah.	

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Asst. Commissioner of Income-tax of the Range from which the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred, shall from the date this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Asst. Commissioner of the Range to whom the said circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 16-8-73.

EXPLANATORY NOTE:

The amendments have become necessary on account of re-allocation of jurisdiction of the Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax in the charges of Andhra Pradesh.

(This note does not form a part of the notification but is intended to be merely clarificatory)

[No. 434/F.No. 261/12/73-ITJ]

क्रा० प्र० 1146.— केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का धोर उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संवत् में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए, निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक प्राय-कर प्रायुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन प्राय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में प्राय-कर और अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :

अनुसूची

रेंज	प्राय-कर सर्किल, वार्ड और जिले
(1)	(2)
विशेष रेंज, हन्दौर	(1) प्राय-कर अधिकारी, केन्द्रीय सर्किल, हन्दौर (2) प्राय-कर अधिकारी, क-वार्ड, हन्दौर (3) प्राय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, हन्दौर (4) प्राय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, हन्दौर (5) प्राय-कर अधिकारी, ब-वार्ड, हन्दौर (6) प्राय-कर अधिकारी, विशेष संपदा शुल्क-एवं प्राय-कर सर्किल, हन्दौर । (7) प्राय-कर अधिकारी, विशेष अन्वेषण सर्किल, हन्दौर ।
हन्दौर रेंज I, हन्दौर 1	(1) प्राय-कर अधिकारी, छ-वार्ड, हन्दौर (2) प्राय-कर अधिकारी, ज-वार्ड, हन्दौर (3) प्राय-कर अधिकारी, ड-वार्ड, हन्दौर (4) प्राय-कर अधिकारी, खड़गोल (5) प्राय-कर अधिकारी, महो (6) प्राय-कर अधिकारी, झ-वार्ड, हन्दौर (7) प्राय-कर अधिकारी, धार
हन्दौर रेंज-II, हन्दौर	(1) प्राय-कर अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण सर्किल हन्दौर (2) प्राय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, हन्दौर (जैसा वह 15 जून, 1972 तक विद्यमान है) (3) प्राय-कर अधिकारी, प्रशासन, हन्दौर (4) प्राय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, हन्दौर (5) प्राय-कर अधिकारी, ज-वार्ड, हन्दौर (6) प्राय-कर अधिकारी, ट-वार्ड, हन्दौर (7) प्राय-कर अधिकारी, ठ-वार्ड, हन्दौर (8) प्राय-कर अधिकारी, व-वार्ड, हन्दौर (9) प्राय-कर अधिकारी, त-वार्ड, हन्दौर (10) प्राय-कर अधिकारी, थ-वार्ड, हन्दौर (11) प्राय-कर अधिकारी, द-वार्ड, हन्दौर (12) प्राय-कर अधिकारी, क-वार्ड, रतलाम (13) प्राय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, रतलाम (14) प्राय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, रतलाम

1	2	1	2
	(15) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, मन्दसौर		(4) आय-कर अधिकारी, ड-वार्ड, जबलपुर
	(16) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, मन्दसौर		(5) आय-कर अधिकारी, च-वार्ड, जबलपुर
	(17) आय-कर अधिकारी, मन्दसौर ।		(6) आय-कर अधिकारी, छ-वार्ड, जबलपुर
उज्जैन रेंज, उज्जैन	(1) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, उज्जैन		(7) आय-कर अधिकारी, ज-वार्ड, जबलपुर
	(2) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, उज्जैन		(8) आय-कर अधिकारी, झ-वार्ड, जबलपुर
	(3) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, उज्जैन		(9) आय-कर अधिकारी, ङ-वार्ड, सतना
	(4) आय-कर अधिकारी, घ-वार्ड, उज्जैन		(10) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, सतना
	(5) आय-कर अधिकारी, ङ-वार्ड, उज्जैन		(11) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, सागर
	(6) आय-कर अधिकारी, च-वार्ड, उज्जैन		(12) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, सागर
	(7) आय-कर अधिकारी, देवास ।		(13) आय-कर अधिकारी, घ-वार्ड, सागर
ग्वालियर रेंज, ग्वालियर ।	(1) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, ग्वालियर		(14) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, कटनी
	(2) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, ग्वालियर		(15) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, कटनी
	(3) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, ग्वालियर		(16) आय-कर अधिकारी, दमोह
	(4) आय-कर अधिकारी, घ-वार्ड, ग्वालियर		(17) आय-कर अधिकारी, छिन्दवाड़ा
	(5) आय-कर अधिकारी, ङ-वार्ड, ग्वालियर		(18) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, छिन्दवाड़ा
	(6) आय-कर अधिकारी, च-वार्ड, ग्वालियर		(19) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, छिन्दवाड़ा
	(7) आय-कर अधिकारी, छ-वार्ड, ग्वालियर		(20) आय-कर अधिकारी, बालाघाट
	(8) आय-कर अधिकारी, गुना		
	(9) आय-कर अधिकारी, शिवपुरी		(21) सी०आई०टी०एम०पी० की अधिसूचना
	(10) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, इटासी		फा० सं० 26 / आई० टी० / एम पी / 72
	(11) आय-कर अधिकारी, ठ-वार्ड, इटासी		तारीख 25-7-1972 के अनुसार
विशेष रेंज, भोपाल	(1) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, भोपाल		आय-कर अधिकारी क-वार्ड, कटनी
	(2) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, भोपाल		के आदेशों के विरुद्ध ऐसे मामलों
	(3) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, भोपाल		में जिनमें वर्तमान अधिकारिता आय-कर
	(4) आय-कर अधिकारी, विदिशा ।		अधिकारी ख-वार्ड और ग-वार्ड, कटनी
भोपाल रेंज, भोपाल	(1) आय-कर अधिकारी, घ-वार्ड, भोपाल		में निहित है, सहायक आय-कर आयुक्त
	(2) आय-कर अधिकारी, ङ-वार्ड, भोपाल		(अपील) विशेष रेंज, जबलपुर के
	(3) आय-कर अधिकारी, च-वार्ड, भोपाल		पास संबंधित सभी अपीलों ।
	(4) आय-कर अधिकारी, खण्डवा		
	(5) अपर आय-कर अधिकारी, खण्डवा		(22) सी०आई०टी०एम०पी० की अधिसूचना
	(6) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, खण्डवा		सं० 22/ आई० टी० / एम पी / 72,
	(7) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, खण्डवा		तारीख 25-7-1972 के अनुसार
	(8) आय-कर अधिकारी, बेतुल		आय-कर अधिकारी ख-वार्ड, जबलपुर
विशेष रेंज, जबलपुर	(1) आय-कर अधिकारी, केन्द्रीय सकिल,		द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध, ऐसे
	जबलपुर		मामलों में जिनमें वर्तमान अधिकारिता
	(2) विशेष संपदा शुल्क-एवं-आय-कर सकिल,		आय-कर अधिकारी ज-वार्ड, जबलपुर
	जबलपुर		में निहित है, सहायक आयकर आयुक्त
	(3) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, जबलपुर		(अपील) विशेष रेंज, जबलपुर के
	(4) आय-कर अधिकारी, क-1 वार्ड, जबलपुर		पास संबंधित सभी अपीलों ।
	(5) आय-कर अधिकारी, क-2 वार्ड, जबलपुर		
	(6) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, जबलपुर		(23) सी०आई०टी०एम०पी० की अधिसूचना
	(7) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, सागर		सं० 19/ आई० टी० / एम पी / 72,
	(8) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, कटनी		तारीख 25-7-1972 के अनुसार,
	(9) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, सतना		आय-कर अधिकारी क-वार्ड, सागर के
जबलपुर रेंज, जबलपुर	(1) आय-कर अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण		आदेशों के विरुद्ध ऐसे मामलों में
	सकिल, जबलपुर ।		जिसमें वर्तमान अधिकारिता आय-कर
	(2) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, जबलपुर		अधिकारी, दमोह में निहित है, सहायक
	(3) आय-कर अधिकारी, घ-वार्ड, जबलपुर		आयकर आयुक्त (अपील) विशेष
			रेंज, जबलपुर के पास संबंधित सभी
			अपीलों ।

1	2
रायपुर रेंज, रायपुर	(1) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, रायपुर (2) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, रायपुर (3) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, रायपुर (4) आय-कर अधिकारी, य-वार्ड, रायपुर (5) आय-कर अधिकारी, ड-वार्ड, रायपुर (6) आय-कर अधिकारी, प्रशासन और संग्रहण, रायपुर (7) आय-कर अधिकारी, प्रशासन, रायपुर (8) आय-कर अधिकारी, संग्रहण, रायपुर (9) आय-कर अधिकारी, निर्धारण-I, रायपुर (10) आय-कर अधिकारी, निर्धारण-II, रायपुर (11) आय-कर अधिकारी, निर्धारण-III, रायपुर (12) आय-कर अधिकारी, निर्धारण-IV, रायपुर (13) आय-कर अधिकारी, निर्धारण-V, रायपुर (14) आय-कर अधिकारी, निर्धारण-VI, रायपुर (15) आय-कर अधिकारी, राजनन्दगांव (16) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, राजनन्दगांव (17) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, राजनन्दगांव (18) आय-कर अधिकारी, बिलासपुर (19) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, बिलासपुर (20) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, बिलासपुर (21) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, बिलासपुर (22) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, दुर्ग (23) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, दुर्ग (24) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, दुर्ग (25) आय-कर अधिकारी, रायगढ़ (26) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, रायगढ़ (27) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, रायगढ़ (28) आय-कर अधिकारी, जगबलपुर (29) आय-कर अधिकारी, क-वार्ड, भिलाई (30) आय-कर अधिकारी, ख-वार्ड, भिलाई (31) आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, भिलाई (32) अपर आय-कर अधिकारी, ग-वार्ड, भिलाई।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहां उस आय-कर सफिल वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 1-12-1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 490/फा० सं० 261/2/73-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 30th October, 1973

S.O. 1146.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in

supersession of the previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax and Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:

SCHEDULE

Ranges	Income-tax Circles, Wards & Districts
(1)	(2)
Special Range, Indore.	(1) I.T.O. Central Circle, Indore. (2) I.T.O. A-Ward, Indore. (3) I.T.O. B-Ward, Indore (4) I.T.O. C-Ward, Indore (5) I.T.O. D-Ward, Indore (6) I.T.O. Special Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Indore. (7) I.T.O. Special Investigation Circle, Indore.
Indore Range-I, Indore.	(1) I.T.O. G-Ward, Indore. (2) I.T.O. J-Ward, Indore. (3) I.T.O. M-Ward, Indore. (4) I.T.O. Kharagone (5) I.T.O. Mhow (6) I.T.O. E-Ward, Indore (7) I.T.O. Dhar.
Indore Range-II, Indore.	(1) I.T.O. Special Survey Circle, Indore. (2) I.T.O. B-Ward, Indore (As existing up to 15th June, 1972). (3) I.T.O. Administration, Indore (4) I.T.O. E-Ward, Indore (5) I.T.O. H-Ward, Indore (6) I.T.O. K-Ward, Indore (7) I.T.O. L-Ward, Indore. (8) I.T.O. N-Ward, Indore. (9) I.T.O. P-Ward, Indore. (10) I.T.O. Q-Ward, Indore. (11) I.T.O. R-Ward, Indore. (12) I.T.O. A-Ward, Ratlam. (13) I.T.O. B-Ward, Ratlam (14) I.T.O. C-Ward, Ratlam. (15) I.T.O. A-Ward, Mandsaur (16) I.T.O. B-Ward, Mandsaur (17) I.T.O. Mandsaur.
Ujjain Range, Ujjain.	(1) I.T.O. A-Ward, Ujjain. (2) I.T.O. B-Ward, Ujjain. (3) I.T.O. C-Ward, Ujjain. (4) I.T.O. D-Ward, Ujjain. (5) I.T.O. E-Ward, Ujjain. (6) I.T.O. F-Ward, Ujjain. (7) I.T.O. Dewas.
Gwalior Range, Gwalior.	(1) I.T.O. A-Ward, Gwalior. (2) I.T.O. B-Ward, Gwalior. (3) I.T.O. C-Ward, Gwalior.

(1)	(2)
Gwalior Range, Gwalior	(4) I.T.O. D-Ward, Gwalior. (5) I.T.O. E-Ward, Gwalior. (6) I.T.O. F-Ward, Gwalior. (7) I.T.O. G-Ward, Gwalior. (8) I.T.O. Guna (9) I.T.O. Shivpuri (10) I.T.O. A-Ward, Itarsi. (11) I.T.O. B-Ward, Itarsi.
Special Range, Bhopal	(1) I.T.O. A-Ward, Bhopal. (2) I.T.O. B-Ward, Bhopal. (3) I.T.O. C-Ward, Bhopal. (4) I.T.O. Vidisha.
Bhopal Range, Bhopal	(1) I.T.O. D-Ward, Bhopal. (2) I.T.O. E-Ward, Bhopal. (3) I.T.O. F-Ward, Bhopal. (4) I.T.O. Khandwa (5) Addl. I.T.O. Khandwa. (6) I.T.O. A-Ward, Khandwa. (7) I.T.O. B-Ward, Khandwa. (8) I.T.O. Betul.
Special Range, Jabalpur	(1) I.T.O. Central Circle, Jabalpur. (2) Special Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Jabalpur. (3) I.T.O. A-Ward, Jabalpur. (4) I.T.O. A-1 Ward, Jabalpur. (5) I.T.O. A-2 Ward, Jabalpur. (6) I.T.O. B-Ward, Jabalpur. (7) I.T.O. A-Ward, Sagar. (8) I.T.O. A-Ward, Katni. (9) I.T.O. A-Ward, Satna.
Jabalpur Range, Jabalpur	(1) I.T.O. Special Survey Circle, Jabalpur. (2) I.T.O. C-Ward, Jabalpur. (3) I.T.O. D-Ward, Jabalpur. (4) I.T.O. E-Ward, Jabalpur. (5) I.T.O. F-Ward, Jabalpur. (6) I.T.O. G-Ward, Jabalpur. (7) I.T.O. H-Ward, Jabalpur. (8) I.T.O. J-Ward, Jabalpur. (9) I.T.O. B-Ward, Satna. (10) I.T.O. C-Ward, Satna. (11) I.T.O. B-Ward, Sagar. (12) I.T.O. C-Ward, Sagar. (13) I.T.O. D-Ward, Sagar. (14) I.T.O. B-Ward, Katni. (15) I.T.O. C-Ward, Katni. (16) I.T.O. Damoh. (17) I.T.O. Chindwara. (18) I.T.O. A-Ward, Chindwara. (19) I.T.O. B-Ward, Chindwara. (20) I.T.O. Balaghat. (21) All appeals pending with A.A.C. Special Range, Jabalpur against orders of I.T.O. A-Ward, Katni in cases in which jurisdiction is vested in ITOs B-Ward and C-Ward, Katni as per C.I.T. M.P.'s Notification F.No. 26/IT/MP/72-dated 25-7-1972. (22) All appeals pending with A.A.C. Special Range, Jabalpur against orders passed by I.T.O. B-Ward, Jabalpur in cases in which the present jurisdiction is vested in I.T.O. H-Ward, Jabalpur vide C.I.T. M.P.'s Notification No. 22/IT/MP/72 dated 25-7-1972.

(1)	(2)
Jabalpur Range, Jabalpur	(23) All appeals pending with Special Range, Jabalpur against orders of I.T.O. A-Ward, Sagar in cases in which the present jurisdiction is vested with I.T.O. Damoh vide C.I.T. M.P.'s Notification No. 19/IT/MP/72 dated 25-7-1972.
Raipur Range, Raipur	(1) I.T.O. A-Ward, Raipur. (2) I.T.O. B-Ward, Raipur. (3) I.T.O. C-Ward, Raipur. (4) I.T.O. D-Ward, Raipur. (5) I.T.O. E-Ward, Raipur. (6) I.T.O. Administration & Collection, Raipur. (7) I.T.O. Administration, Raipur. (8) I.T.O. Collection, Raipur. (9) I.T.O. Assessment-I, Raipur. (10) I.T.O. Assessment-II Raipur. (11) I.T.O. Assessment-III, Raipur. (12) I.T.O. Assessment-IV, Raipur. (13) I.T.O. Assessment-V, Raipur. (14) I.T.O. Assessment-VI, Raipur. (15) I.T.O. Rajnandgaon. (16) I.T.O. A-Ward, Rajnandgaon. (17) I.T.O. B-Ward, Rajnandgaon. (18) I.T.O. Bilaspur. (19) I.T.O. A-Ward, Bilaspur. (20) I.T.O. B-Ward, Bilaspur. (21) I.T.O. C-Ward, Bilaspur. (22) I.T.O. A-Ward, Durg. (23) I.T.O. B-Ward, Durg. (24) I.T.O. C-Ward, Durg. (25) I.T.O. Raigarh. (26) I.T.O. A-Ward, Raigarh. (27) I.T.O. B-Ward, Raigarh. (28) I.T.O. Jagdalpur. (29) I.T.O. A-Ward, Bhilai. (30) I.T.O. B-Ward, Bhilai. (31) I.T.O. C-Ward, Bhilai. (32) Addl. I.T.O. C-Ward, Bhilai.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward, District or part thereof is transferred, shall, from the date of this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-12-1973.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on abolition of three Ranges of A.A.Cs. namely Ratlam Range, and Range, II and III Jabalpur and creation of one new Range at Indore in C.I.T.'s charge.

(This does not form a part of the Notification) but is intended to be merely clarificatory)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1973

क्रा० प्रा० 1147.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 424 (फा० सं० 261/10/73-आई टी जे) तारीख 21-7-73 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

उक्त अनुसूची में, क्रम सं० 4 राउरकेला रेंज, राउरकेला के स्थान पर सम्बलपुर रेंज, सम्बलपुर रखा जाए।

यह अधिसूचना 8-11-73 से प्रभावी होगी।

[सं० 497 (फा० सं० 261/10/73-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 9th November, 1973

S.O. 1147.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 424 (F. No. 261/10/73-ITJ) dated 21-7-73 viz :

In the said Schedule at Sr. No. 4 Rourkela Range, Rourkela may be substituted as Sambalpur Range, Sambalpur.

This Notification shall take effect from 9-11-73.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on resignation of A.A.C., Rourkela Range, Rourkela as A.A.C., Sambalpur Range, Sambalpur.

(This does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 497/F.No.261/10/73-ITJ]

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1973

क्रा० प्रा० 1148.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, निवेदन देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन आय-कर सफिलों/वार्डों और जिलों में आय-कर या अधिकतर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर वार्ड/सफिल और जिले
1	2	3
1.	विशेष रेंज-II, मुम्बई	केवल कम्पनी सफिल I (1), I (2) और I (3) के आय-कर अधिकारी के प्रभार।
2.	विशेष रेंज-II, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी I (1), I (2), I (3), I (4) और I (9) के प्रभारों के सिवाए कम्पनी सफिल-I (2) बी०आर०सी० का आय-कर अधिकारी-I

1	2	3
3.	विशेष रेंज-III, मुम्बई	(1) केवल कम्पनी सफिल-I (4) और I (9) के आय-कर अधिकारी के प्रभार। (2) फिल्म सफिल के आय-कर अधिकारी।
4.	क-रेंज, मुम्बई	(1) मुम्बई सफिल। (2) एन०आर०आर०सी०। (3) वेतन शाखा-II (4) विदेश अनुभाग (5) वि०अ०शा० के आय-कर अधिकारी 1 से 6 (6) वेतन शाखा-I (7) आय-कर अधिकारी 1 के सिवाए बी०आर०सी०। (8) म-वार्ड-I
5.	विशेष रेंज-VII, मुम्बई	(1) केवल कम्पनी सफिल-II (1), II (3), और II (5) के आय-कर अधिकारी के प्रभार। (2) आय-कर अधिकारी, वि०अ०शा०-VII
6.	विशेष रेंज-XVI, मुम्बई	(1) घ-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 3। (2) घ-I वार्ड के आय-कर अधिकारी 1,2,3, 17,18,19, और 20। (3) ग-V वार्ड के आय-कर अधिकारी 1,2,9,14 और 15। (4) ग-IV वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5 और 10।
7.	विशेष रेंज-XVII, मुम्बई	II (1), II (3) और II (5) के सिवाए कम्पनी सफिल-II के सभी आय-कर अधिकारी।
8.	च-रेंज, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1,2,3,17,18,19-और 20 के प्रभारों के सिवाए च-I वार्ड। (2) आय-कर अधिकारी 1,2 और 3 के प्रभारों के सिवाए घ-II वार्ड। (3) आय-कर अधिकारी 1,2,9,14 और 15 के प्रभारों के सिवाए ग-V वार्ड। (4) आय-कर अधिकारी 1 से 5 और 10 के प्रभारों के सिवाए ग-IV वार्ड।
9.	विशेष रेंज-IX, मुम्बई	(1) क-III वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5। (2) क-IV वार्ड के आय-कर अधिकारी 1,2,3 और 8। (3) क-V वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 4,6 और 10।
10.	विशेष रेंज-XIII, मुम्बई	केवल कम्पनी सफिल-III (1) से III (7) के आय-कर अधिकारी के प्रभार।
11.	विशेष रेंज-XIV, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 7 के प्रभारों के सिवाए कम्पनी सफिल-III। (2) क-I वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 6।

1	2	3
		(3) क-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5।
12. विशेष रेंज-XV, मुम्बई	(1) हुन्डी सकिल के सभी आय-कर अधिकारी	
	(2) ग-I वार्ड के सभी आय-कर अधिकारी।	
13. ग-रेंज, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 6 के प्रभारों के सिवाए क-I वार्ड।	
	(2) आय-कर अधिकारी 1 से 5 के प्रभारों के सिवाए क-III वार्ड।	
	(3) आय-कर अधिकारी 1 से 4, 6 और 10 के प्रभारों के सिवाए क-V वार्ड।	
	(4) आय-कर अधिकारी 1 से 5 के प्रभारों के सिवाए क-II वार्ड।	
	(5) आय-कर अधिकारी 1,2,3 और 8 के प्रभारों के सिवाए क-IV वार्ड।	
14. विशेष रेंज IV, मुम्बई	केवल कम्पनी सकिल-IV (1) से IV (7) के आय-कर अधिकारी के प्रभार।	
15. विशेष रेंज-V, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 7 के प्रभारों के सिवाए कम्पनी सकिल-IV	
	(2) ग-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 8।	
	(3) ग-III वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 4।	
16. घ-रेंज, मुम्बई।	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 8 के प्रभारों के सिवाए ग-II वार्ड।	
	(2) निष्कास्त सकिल-I	
	(3) आय-कर अधिकारी 1 से 4 के प्रभारों के सिवाए ग-III वार्ड।	
17. विशेष रेंज-VI, मुम्बई	(1) ख-III वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 6, 16 और 17।	
	(2) मार्केट वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5।	
	(3) ख-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 4।	
18. विशेष रेंज-VIII, मुम्बई	(1) कम्पनी सकिल-V के सभी आय-कर अधिकारी।	
	(2) ख-I वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 3।	
19. छ-रेंज, मुम्बई	(1) निष्कास्त सकिल-II	
	(2) आय-कर अधिकारी 1 से 3 के प्रभारों के सिवाए ख-I वार्ड।	
	(3) आय-कर अधिकारी 1 से 5 के प्रभारों के सिवाए मार्केट वार्ड।	
	(4) आय-कर अधिकारी 1 से 4 के प्रभारों के सिवाए ख-II वार्ड।	
	(5) आय-कर अधिकारी 1 से 6, 16 और 17 के प्रभारों के सिवाए ख-III वार्ड।	
20. छ-रेंज, मुम्बई।	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 9 के प्रभारों के सिवाए छ-वार्ड।	

1	2	3
		(2) आय-कर अधिकारी 1 से 4 और 9 के प्रभारों के सिवाए बी० एम० डी० (पश्चिम)।
21. विशेष रेंज-X, मुम्बई	(1) कम्पनी सकिल-VI, मुम्बई के सभी आय-कर अधिकारी।	
	(2) छ-वार्ड के आय-कर अधिकारी 1,2,8 और 9।	
22. विशेष रेंज-XI, मुम्बई	बी०एस०डी० (पश्चिम) के आय-कर अधिकारी 1 से 4 और 9 के प्रभार।	
23. विशेष रेंज-XII, मुम्बई	(1) बी०एस०डी० (पूर्व) के आय-कर अधिकारी 1,2,3,6 और 10 के प्रभार।	
	(2) छ-वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 3।	
	(3) ड-वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 9।	
24. ड-रेंज, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 3 प्रभारों के सिवाए छ-वार्ड।	
	(2) आय-कर अधिकारी 1,2,8 और 9 के प्रभारों के सिवाए छ-वार्ड।	
	(3) आय-कर अधिकारी 1,2,3,6 और 10 के प्रभारों के सिवाए बी० एस० डी० (पूर्व)	

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहाँ उस आय-कर सकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी जो उनके संबंध में कार्यवाही ही करेगा।

यह अधिसूचना 1-12-1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 507/फा० सं० 261/5/73-आई० टी० जे०]

New Delhi, 30th November, 1973

S.O.1148.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles/Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sr. No.	RANGE	Income-tax Ward/Circle & Districts.
1	2	3
1.	Special Range-I, Bombay.	Companies Circle I (1), I (2) & I (3) ITOS Charges only.
2.	Special Range-II, Bombay	(1) Companies Circle-I except I(1), I(2), I(3), I(4) & I(9) ITOS Charges. (2) 1st I.T.O. of B.R.C.

1	2	3
3. Special Range-III, Bombay.		(1) Companies Circle-I(4) & II(9) ITOs Charges only. (2) I.T.Os of Film Circle.
4. A-Range, Bombay.		(1) Bombay Circle. (2) N.R.R.C. (3) Salaries Branch-II. (4) Foreign Section. (5) I.T.Os of S.I.B. I to VI. (6) Salaries Branch-I (7) B.R.C. except 1st I.T.O. (8) X-Ward.
5. Special Range-VII, Bombay.		(1) Companies Circle II(1) II(3) & II(5) ITOs Charges only. (2) ITO: S.I.B. VII.
6. Special Range-XVI, Bombay.		(1) 1st to 3rd ITOs of D-II Ward. (2) 1st, 2nd, 3rd, 17th, 18th, 19th & 20th ITOs of D-I Ward. (3) 1st, 2nd, 9th, 14th & 15th ITOs of C-V Ward. (4) 1st to 5th & 10th ITOs of C-IV Ward.
7. Special Range-XVII, Bombay.		All ITOs in Companies Circle-II except II(1), II(3) & II(5).
8. F-Range, Bombay.		(1) D-I Ward except 1st, 2nd, 3rd, 17th, 18th, 19th & 20th ITOs charges. (2) D-II Ward except 1st, 2nd & 3rd ITOs Charges. (3) C-V Ward except 1st, 2nd, 9th, 14th & 15th ITOs Charges. (4) C-IV Ward except 1st to 5th & 10th ITOs Charges.
9. Special Range-IX, Bombay.		(1) 1st to 5th ITOs of A-III Ward. (2) 1st, 2nd, 3rd & 8th ITOs of A-IV Ward. (3) 1st to 4th, 6th & 10th ITOs of A-V Ward.
10. Special Range-XIII, Bombay.		Companies Circle-III(1), to III(7) ITOs Charges only.
11. Special Range-XIV, Bombay.		(1) Companies Circle-III except 1st to 7th ITOs Charges. (2) 1st to 6th ITOs of A-I Ward. (3) 1st to 5th ITOs of A-II Ward.
12. Special Range-XV, Bombay.		(1) All ITOs of Hundi Circle. (2) All I.T.Os of C-I Ward.
13. C-Range, Bombay.		(1) A-I Ward, except 1st to 6th ITOs Charges. (2) A-III Ward except 1st to 5th ITOs Charges. (3) A-V Ward except 1st to 4th, 6th, and 10th ITOs Charges. (4) A-II Ward except 1st to 5th ITOs Charges. (5) A-IV Ward except 1st, 2nd, 3rd, & 8th ITOs Charges.
14. Special Range-IV, Bombay.		Companies Circle-IV(1) to IV(7) ITOs Charges only.
15. Special Range-V, Bombay.		(1) Companies Circle-IV except 1st to 7th I.T.Os Charges. (2) 1st to 8th I.T.Os of C-II Ward. (3) 1st to 4th I.T.Os of C-III Ward.

1	2	3
16. D-Range, Bombay.		(1) C-II Ward except 1st to 8th ITOs Charges (2) Evacuees Circle-I. (3) C-III Ward, except 1st to 4th ITOs Charges.
17. Special Range-VI, Bombay.		(1) 1st to 6th, 16th & 17th ITOs of B-III Ward. (2) 1st to 5th ITOs of Market Ward. (3) 1st to 4th ITOs of B-II Ward.
18. Special Range-VIII, Bombay.		(1) All ITOs of Companies Circle-V. (2) 1st to 3rd I.T.Os of B-I Ward.
19. B-Range, Bombay.		(1) Evacuees Circle-II. (2) B-I Ward except 1st to 3rd ITOs Charges. (3) Market Ward except 1st to 5th ITOs Charges. (4) B-II Ward except 1st to 4th ITOs Charges. (5) B-III Ward except 1st to 6th, 16th & 17th ITOs Charges.
20. G-Range, Bombay.		(1) E-Ward except 1st to 9th ITOs charges. (2) B.S.D. (West) except 1st to 4th & 9th ITOs Charges.
21. Special Range-X, Bombay.		(1) All ITOs of Companies Circle-VI, Bombay. (2) 1st, 2nd, 8th & 9th ITOs of GA-Ward.
22. Special Range-XI, Bombay.		1st to 4th & 9th ITOs Charges of BSD (West).
23. Special Range-XII, Bombay.		(1) 1st, 2nd, 3rd, 6th & 10th ITOs of B.S.D. (East). (2) 1st to 3rd I.T.Os of G-Ward. (3) 1st to 9th ITOs of E-Ward.
24. E-Range, Bombay.		(1) G-Ward, except 1st to 3rd ITOs Charges. (2) GA-Ward, except 1st, 2nd, 8th & 9th ITOs Charges. (3) B.S.D. (East) except 1st, 2nd, 3rd, 6th & 10th ITOs Charges.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range appeals arising out of assessments made in that Income-tax, Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-12-1973.

[No. 507 F.No. 261/5/73-ITJ].

Explanatory Note :

The amendment has become necessary on account of revision of AAC's jurisdiction in Bombay City Charges.

[This does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory].

C.V. PADMANABHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1973

आय-कर

का० आ० 1149 . —केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसकी समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन आय-कर सफिलों/वार्डों और जिलों में आय-कर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर वार्ड/सफिल और जिले
1	2	3
1.	विशेष रेंज-I, मुम्बई	केवल आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन कम्पनी सफिल-I (1), I(2) और I(3)।
2.	विशेष रेंज-II, मुम्बई	(1) सिवाए I(1), I(2), I(3), I(4) और I(9) के आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन कम्पनी सफिल-I। (2) बी०आर०सी० का आय-कर अधिकारी -1
3.	विशेष रेंज-III, मुम्बई	(1) केवल आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन कम्पनी सफिल-I(4) और I(9) (2) फ़िल्म सफिल के आय-कर अधिकारी।
4.	क-रेंज, मुम्बई	(1) मुम्बई सफिल। (2) एन०आर०आर०सी०। (3) बेतन-शाखा-II (4) विदेश अनुभाग (5) विशेष अन्वेषण शाखा के आय-कर अधिकारी 1 से 6 (6) बेतन शाखा-I (7) आय कर अधिकारी 1 के सिवाए बी०आर०सी० (8) भ-वार्ड
5.	विशेष रेंज-VII, मुम्बई	(1) केवल आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन कम्पनी सफिल-II(1), II(3) और (5) II (2) आय-कर अधिकारी, वि०अ०शा० VII
6.	विशेष रेंज-XVI, मुम्बई	(1) घ-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 3 (2) घ-I वार्ड के आय-कर अधिकारी 1, 2, 3, 17, 18, 19 और 20 (3) ग-V वार्ड के आय-कर अधिकारी 1, 2, 9, 14 और 15 (4) ग-IV वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5 और 10।
7.	विशेष रेंज-XVII, मुम्बई	II(1), II(3) और II(5) के सिवाए कम्पनी सफिल-II के सभी आय-कर अधिकारी।

1	2	3
8.	च-रेंज, मुम्बई	(1) आयकर अधिकारी 1, 2, 3, 17, 18, 19 और 20 के प्रभार के सिवाय-I वार्ड। (2) आय-कर अधिकारी 1, 2 और 3 के प्रभार के सिवाय घ-II वार्ड (3) आय-कर अधिकारी 1, 2, 9, 14 और 15 के प्रभार के सिवाय ग-V वार्ड। (4) आय-कर अधिकारी 1 से 5 और 10 के प्रभार के सिवाय ग-IV वार्ड।
9.	विशेष रेंज-IX, मुम्बई	(1) क-III वार्ड के आयकर अधिकारी 1 से 5। (2) क-IV वार्ड के आय-कर अधिकारी 1, 2, 3, और 8 (3) क-V वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 4, 6 और 10
10.	विशेष रेंज-XIII, मुम्बई	केवल आय-कर अधिकारियों के प्रभाराधीन कम्पनी सफिल-III (1) से III(7)
11.	विशेष रेंज-XIV, मुम्बई	(1) आयकर अधिकारी 1 से 7 के प्रभार के सिवाए कम्पनी सफिल-III (2) क-I वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 6 (3) क-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5।
12.	विशेष रेंज-XV, मुम्बई	(1) हुण्टी सफिल के सभी आय-कर अधिकारी (2) ग-I वार्ड के सभी आय-कर अधिकारी
13.	ग-रेंज, मुम्बई	(1) आयकर अधिकारी 1 से 6 के प्रभार के सिवाए क-1 वार्ड। (2) आयकर अधिकारी 1 से 5 के प्रभार के सिवाए क-III वार्ड। (3) आयकर अधिकारी 1 से 4, 6 से 10 के प्रभार के सिवाए क-V वार्ड (4) आय-कर अधिकारी 1 से 5 के प्रभार के सिवाए क-II वार्ड। (5) आय-कर अधिकारी 1, 2, 3 और 8 के प्रभार के सिवाए क-IV वार्ड।
14.	विशेष रेंज-IV, मुम्बई	केवल आय-कर अधिकारी कम्पनी सफिल-IV(1) से IV(7) के प्रभार
15.	विशेष रेंज-V, मुम्बई	(1) केवल आय-कर अधिकारी 1 से 7 के प्रभारों के सिवाए कम्पनी सफिल-IV (2) ग-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 8। (3) ग-III वार्ड के आयकर अधिकारी 1 से 4।
16.	घ-रेंज, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 8 के प्रभारों के सिवाए ग-II वार्ड।

1	2	3
	(2) निष्कांत सफिल-I	
	(3) आय-कर अधिकारी 1 से 4 के प्रभारों के सिवाय ग-III वार्ड ।	
17. विशेष रेंज-6, मुम्बई	(1) ख-III वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 6, 16 और 17 ।	
	(2) मार्केट वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 5 ।	
	(3) ख-II वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 4 ।	
18. विशेष रेंज-8, मुम्बई	(1) कम्पनी सफिल-V के सभी आय-कर अधिकारी ।	
	(2) ख-I वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 3 ।	
19. ख-रेंज, मुम्बई	(1) निष्कांत सफिल-II	
	(2) आय-कर अधिकारी 1 से 3 के प्रभारों के सिवाय ख-I वार्ड	
	(3) आय-कर अधिकारी 1 से 5 के प्रभारों के सिवाय मार्केट वार्ड ।	
	(4) आय-कर अधिकारी 1 से 4 के प्रभारों के सिवाय ख-II वार्ड ।	
	(5) आय-कर अधिकारी 1 से 6, 16 और 17 के प्रभारों के सिवाय ख-III वार्ड ।	
20. ज-रेंज, मुम्बई	ड-वार्ड, मुम्बई के सभी आय-कर अधिकारी ।	
21. विशेष रेंज-10, मुम्बई	(1) कम्पनी सफिल-6, मुम्बई के सभी आय-कर अधिकारी ।	
	(2) क-वार्ड के आय-कर अधिकारी 1, 2 8 और 9 ।	
22. विशेष रेंज-11, मुम्बई	बी एस डी (पश्चिम) के आय-कर अधिकारी 1 से 4 और 9 ।	
23. विशेष रेंज-12, मुम्बई	(1) बी एस डी (पूर्व) के आय-कर अधिकारी 1, 2, 3, 6 और 10 ।	
	(2) छ-वार्ड के आय-कर अधिकारी 1 से 3 ।	
24. ड-रेंज, मुम्बई	(1) आय-कर अधिकारी 1 से 3 के प्रभारों के सिवाय छ-वार्ड ।	
	(2) आय-कर अधिकारी 1, 2, 8 और 9 के प्रभारों के सिवाय छ-वार्ड ।	
	(3) आय-कर अधिकारी 1, 2, 3, 6 और 10 के प्रभारों के सिवाय बी०एस० डी० (पूर्व) ।	
25. छ-रेंज, मुम्बई	आय-कर अधिकारी 1 से 4 और 9 के प्रभारों के सिवाय बी०एस०डी० (पश्चिम)	

(प्रपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (प्रपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 14-12-73 से प्रभावी होगी ।

[सं० 518/फा० सं० 261/5/73-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 13th December, 1973

INCOME TAX

S. O. 1149.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super tax in the Income-tax Circles/Wards and Districts, specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sr. No.	Range	Income-tax Ward/Circle and Districts.
1	2	3
1.	Special Range-I, Bombay.	Companies Circle-I (1), I(2) & I(3) ITOs Charges only.
2.	Special Range-II, Bombay.	(1) Companies Circle-I except I(1), I(2), I(3) I(4) & I(9) ITOs charges. (2) 1st I.T.O. of B.R.C.
3.	Special Range-III, Bombay.	(1) Company Circle-I(4) & I(9) ITOs charges only. (2) I.T.Os. of Film Circle.
4.	A-Range, Bombay.	(1) Bombay Circle. (2) N.R.R.C. (3) Salaries Branch-II. (4) Foreign Section. (5) I.T.Os. of S.I.B. I to VI. (6) Salaries Branch-I. (7) B.R.C. except 1st I.T.O. (8) X-Ward.
5.	Special Range-VII, Bombay.	(1) Companies Circle-II(1), II(3) & II(5) ITOs charges only. (2) I.T.O. S.I.B. VII.
6.	Special Range-XVI, Bombay.	(1) 1st to 3rd I.T.Os. of D-II Ward. (2) 1st, 2nd, 3rd, 17th, 18th, 19th & 20th I.T.Os. of D-I Ward. (3) 1st, 2nd, 9th, 14th & 15th ITOs of C-V Ward. (4) 1st to 5th & 10th ITOs of C-IV Ward.
7.	Special Range-XVII, Bombay	All I.T.Os. in Companies Circle-II except II(1), II(3) & II(5).
8.	F-Range, Bombay.	(1) D-I Ward except 1st, 2nd, 3rd, 17th, 18th, 19th & 20th ITOs charges. (2) D-II Ward except 1st, 2nd, & 3rd ITOs charges. (3) C-V Ward except 1st, 2nd, 9th, 14th & 15th I.T.Os. charges. (4) C-IV Ward except 1st to 5th & 10th I.T.Os charges.

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहाँ उस आय-कर सफिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निष्पत्तियों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त

1	2	3
9. Special Range-IX, Bombay.	(1) 1st to 5th I.T.Os. of A-III Ward. (2) 1st, 2nd, 3rd & 8th ITOs of A-IV Ward. (3) 1st to 4th, 6th & 10th ITOs of A-V Ward.	
10. Special Range-XIII, Bombay.	Companies Circle-III(1) to III(7) I.T.Os charges only.	
11. Special Range-XIV, Bombay.	(1) Companies Circle-III except 1st to 7th I.T.Os charges. (2) 1st to 6th ITOs of A-I Ward. (3) 1st to 5th ITOs of A-III Ward.	
12. Special Range-XV, Bombay.	(1) All I.T.Os. of Hindi Circle. (2) All I.T.Os of C-I, Ward.	
13. C-Range, Bombay.	(1) A-I Ward except 1st to 6th I.T.Os charges. (2) A-III Ward except 1st to 5th I.T.Os charges. (3) A-V Ward except 1st to 4th, 6th & 10th I.T.Os charges. (4) A-II Ward except 1st to 5th I.T.Os charges. (5) A-IV Ward except 1st, 2nd, 3rd & 8th I.T.Os.charges.	
14. Special Range-IV, Bombay.	Companies Circle-IV (1) to IV(7) I.T.Os charges only.	
15. Special Range-V, Bombay.	(1) Companies Circle-IV except 1st to 7th I.T.Os. charges only. (2) 1st to 8th I.T.Os of C-II Ward. (3) 1st to 4th I.T.Os of C-III Ward.	
16. D-Range, Bombay.	(1) C-II Ward except 1st to 8th I.T.Os charges. (2) Evacuees Circle-I. (3) C-III Ward except 1st to 4th ITOs charges.	
17. Special Range-VI, Bombay.	(1) 1st to 6th, 16th & 17th ITOs of B-III Ward. (2) 1st to 5th ITOs of Market Ward. (3) 1st to 4th ITOs of B-II Ward.	
18. Special Range-VIII, Bombay.	(1) All ITOs of Companies Circle-V. (2) 1st to 3rd ITOs of B-I Ward.	
19. B-Range, Bombay.	(1) Evacuees Circle-II. (2) B-I Ward except 1st to 3rd ITOs charges. (3) Market Ward except 1st to 5th ITOs charges. (4) B-II Ward except 1st to 4th ITOs charges. (5) B-III Ward except 1st to 6th, 16th & 17th ITOs charges.	
20. H-Range, Bombay.	All I.T.Os of E-Ward, Bombay.	
21. Special Range-X, Bombay.	(1) All I.T.Os of Companies Circle-VI, Bombay. (2) 1st, 2nd, 8th & 9th ITOs of GA-Ward.	
22. Special Range-XI, Bombay.	1st to 4th & 9th I.T.O. charges of BSD (WEST).	
23. Special Range-XII, Bombay.	(1) 1st, 2nd, 3rd, 6th & 10th ITOs of BSD (EAST). (2) 1st to 3rd ITOs of G-Ward.	
24. E-Range, Bombay.	(1) G-Ward except 1st to 3rd ITOs charges.	

1	2	3
		(2) GA-Ward except 1st, 2nd, 8th & 9th ITOs charges. (3) B.S.D. (EAST) except 1st, 2nd, 3rd, 6th & 10th I.T.Os. charges.
25. G-Range, Bombay.	B.S.D. (WEST) except 1st to 4th & 9th ITOs charges.	

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 14-12-73.

Explanatory Note :

The Amendment has become necessary consequent on creation of one new Range namely 'H-Range' Bombay in C.I.T.'s charge.

(This note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 518/F. No. 261/5/73-ITJ]

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1974

आय-कर

क्रा० आ० 1150.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थायी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उन आय-कर सक्तियों/वाहों और जिलों में आय-कर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर सक्तिल, वाहें या जिले
1	2	3
1. कटक रेंज, कटक		(i) केन्द्रीय सक्तिल, कटक (ii) विशेष सक्तिल, कटक (iii) कटक सक्तिल, कटक (iv) डेंकानाल सक्तिल (v) बालासोर सक्तिल (vi) बारीपादा सक्तिल
2. बेरहामपुर रेंज, बेरहामपुर ।		(i) बेरहामपुर सक्तिल (ii) पुरी सक्तिल (iii) भुवनेश्वर सक्तिल (iv) संपदा शुल्क सक्तिल, कटक (v) बोखंगीर सक्तिल

1	2	3
	(vi) भवानी पटना सक्ति	
	(vii) जेपूर सक्ति	
3. सम्बलपुर रेंज, सम्बलपुर	(i) सम्बलपुर सक्ति	
	(ii) झारसुगुडा सक्ति	
	(iii) राउरकेला सक्ति	
	(iv) कूनभार सक्ति	

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सक्ति, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहां उस आय-कर सक्ति वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सक्ति, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सक्ति, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएंगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 21-4-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 543/फा० सं० 261/10/73 आई० टी० जे०]

सी० बी० पदमानाभन्, अवसर सचिव

New Delhi, the 18th January, 1974

S. O. 1150.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards of Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof:—

SCHEDULE

Sr. No.	Range	Income-tax Circle, Wards or Districts
1. Cuttack Range	Cuttack.	(i) Central Circle, Cuttack. (ii) Special Circle Cuttack. (iii) Cuttack Circle, Cuttack. (iv) Dhenkanal Circle. (v) Balasore Circle. (vi) Baripada Circle.
2. Berhampur Range, Berhampur.		(i) Berhampur Circle. (ii) Puri Circle. (iii) Bhubaneswar Circle. (iv) Estate Duty Circle, Cuttack. (v) Bolangir Circle. (vi) Bhawanipatna Circle. (vii) Joypore Circle.
3. Sambalpur Range, Sambalpur.		(i) Sambalpur Circle. (ii) Jharsuguda Circle. (iii) Rourkela Circle. (iv) Keonjhar Circle.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of the notification before the Appellate Asstt. Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this Notification shall take effect, be transferred to and dealt

with by the Appellate Asstt. Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 21-4-1974.

[No. 543/F. No. 261/10/73-ITJ]
C.V. PADMANABHAN, Under Secy.

Explanatory Note :

This amendment has become necessary on account of abolition of one of the posts of A.A.C. and on consequent reorganisation of work.

(This does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

बंगलूर, 13 फरवरी, 1975

का० आ० 1151:—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, एतद्वारा, बंगलूर के सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बंगलूर बन्दरगाह से किये जाने वाले निर्यात के सम्बन्ध में, उक्त नियमावली के 189 क के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूँ।

[सं० 1/1975]

ई० आर० श्रीकण्ठईया, समाहर्ता

OFFICE OF THE CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Bangalore, the 13th February, 1975

S.O. 1151.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Assistant Collector of Central Excise, Mangalore to exercise the powers of Collector under Rule 189-A of Central Excise Rules, 1944 in regard to exports through Mangalore Port.

[No. 1/1975]

E. R. SRIKANTIA, Collector

आयकर आयुक्त कार्यालय, दिल्ली (केन्द्रीय)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1975

का० आ० 1152. —आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अनुसार, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बोमा विभाग), नई दिल्ली के आदेश एफ० सं० 16-/202/67-आई० टी० बी० दिनांक 25 मार्च, 1969 के द्वारा प्राधिकृत तथा निर्देशित निम्न लिखित निर्धारितियों, जिन पर वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन 5,000/- रु० से कम नहीं का अर्थदण्ड लगाया गया तथा निर्धारित अवधि में उन्होंने आयकर अपीलीय अधिकरण को कोई अपील नहीं की या आपात की तो उसका निपाटन कर दिया गया, के नाम और उनसे संबंधित अन्य विनिर्दिष्ट विवरणों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 1973-74

क्रमांक	निर्धारित का नाम व पता	प्राप्ति तिथि वर्ष	निर्धारण वर्ष	अर्थ-वर्ष की राशि	चूक का स्वरूप
1.	श्री गौरी शंकर, 279-मस्जिद मोठ, नई दिल्ली	हि०प्र०कु० 1968-69	रु० 6,183	धारा 142(1) या 143(2) के अधीन नोटिस का अपालन।	
2.	मसर्स जगदीश प्रसाद बाबू राम, 2703, गली पट्टी वाली, नया बाजार दिल्ली	व्यष्टि 1967-68	रु० 21,064	कुल आय की विवरणी निर्धारित अवधि में दाखिल न करना।	
		वर्षी	रु० 52,662	धारा 142(1) या 143(2) के अधीन नोटिस का अपालन।	
3.	पंडित लीला राम, सी-6/4, माडल टाउन, दिल्ली	हि०प्र०कु० 1969-70	रु० 6,000/-	अग्रिम कर का गलत अनुमान दाखिल करना।	
4.	मसर्स मदन मोहन दम्मा-मल (विघटित फर्म), फिरोजाबाद (यूपी०)	1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64	रु० 5,258 रु० 9,916 रु० 21,846 रु० 15,411 रु० 23,032 रु० 6,848	आय का छुपाना—बही—बही—बही—बही—बही—	
5.	मसर्स मनोहर लाल राजन-विनायक, 57, राजपुर रोड, देहरादून, (यूपी०)	1970-71	रु० 6,592	कुल आय की विवरणी निर्धारित अवधि में दाखिल न करना।	
6.	श्री मुकेश कुमार जैन, 110-डी, कमला नगर, दिल्ली	व्यष्टि 1971-72	रु० 6,000	अग्रिम कर का गलत अनुमान दाखिल करना।	

[सं० I (एफ० सं० सी० आई० टी० (सी०)/सुपर/(16)/74-75/आयकर]

एम० एस० शिवरामकृष्णा, आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF INCOME TAX
DELHI (CENTRAL)

New Delhi, the 3rd April, 1975

names and other specified particulars relating to the assesses on whom a penalty of not less than Rs. 5000/- was imposed under the provisions of the Income-tax Act, 1961, during the Financial year 1973-74 where no appeal to the Income-tax Appellate Tribunal was presented within the time allowed or the appeal, if presented, has been disposed of, are hereby published.

FINANCIAL YEAR 1973-74

S. No.	Name & address of the assessee	Status	Asstt. year	Amount of penalty	Nature of default
				Rs.	
1.	Sh. Gauri Shanker 279, Masjid Moth, New Delhi.	H.U.F.	1968-69	6,183	Non-compliance of notice u/s 142(1) or 143(2).
2.	M/s. Jagdish Prasad Babu Ram, 2703, Gali, Pattiwali, Naya Bazar, Delhi.	Indl.	1967-68	21,064	Failure to file return of total income in time.
			1967-68	52,662	Non-compliance of notice u/s 142(1) or 143(2).
3.	Pt. Lila Ram, C-6/4, Model Town, Delhi.	H.U.F.	1969-70	6,000	Filing of wrong estimate of advance-tax.
4.	M/s. Madan Mohan Dammam (Dissolved firm) Firozabad, (U.P.)	Firm	1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64	5,258 9,916 21,846 15,411 23,032 6,848	Concealment of income. Do. Do. Do. Do. Do.
5.	M/s. Manohar Lal Rajanvinyak, 57, Rajpur Road, Dehradun, (U.P.)	Firm	1970-71	6,592	Failure to file return of total income in time.
6.	Sh. Mukesh Kumar Jain, 110-D, Kamla Nagar, Delhi.	Indl.	1971-72	6,000	Filing of wrong estimate of advance-tax.

[No.I(F. No. CIT (C)/SUPER/(16)/74-75/I.T.)
M. S. SIVARAMAKRISHNA, Commissioner.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1975

क्रा० प्रा० 1153.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री जी० बी० तनेजा की 1 अप्रैल, 1975 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/8/74-बी० ओ० I-I(i)]

(Department of Banking)
New Delhi, the 31st March, 1975

S.O. 1153.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised

S.O. 1152.—As authorised and directed by the Central Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance), New Delhi's Order F. No. 16/202/67-IT(B) dated 25th March, 1969, in terms of section 287 of the Income-tax Act 1961, the

Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri D. V. Taneja as the Managing Director of Central Bank of India for the period commencing on 1st April, 1975 and ending with 30th April, 1975.

[No. F. 9/6/74-BO. I-1 (i)]

का०प्रा० 1154.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री डी० वी० तनेजा को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1975 से सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-2(i)]

S.O. 1154.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri D. V. Taneja, who has been reappointed as Managing Director of Central Bank of India with effect from 1st April, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Central Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/6/74-BO. I-2(i)]

का०प्रा० 1155.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री बी० डी० ठक्कर को 1 अप्रैल, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिये बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-1-(4)]

S.O. 1155.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri V. D. Thakkar as the Managing Director of Bank of Baroda for a further period commencing on 1st April, 1975 and ending with 30th April, 1975.

[No. F. 9/6/74-BO. I-1 (iv)]

का०प्रा० 1156.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री बी० डी० ठक्कर को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1975 से बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-2 (4)]

S.O. 1156.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri V. D. Thakkar, who has been re-appointed as Managing Director of Bank of Baroda with effect from 1st April, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Bank of Baroda with effect from the same date.

[No. F. 9/6/74-BO. I-2 (iv)]

का०प्रा० 1157.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री बी० आर० देसाई को 1 अप्रैल, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिये, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के प्रबन्ध-निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-1 (5)]

S.O. 1157.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri V. R. Desai as the Managing Director of United Commercial Bank for a further period commencing on 1st April, 1975 and ending with 30th April, 1975.

[No. F. 9/6/74-BO. I-1(v)]

का०प्रा० 1158.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री बी० आर० देसाई को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1975 से यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-2 (5)]

S.O. 1158.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri V. R. Desai, who has been re-appointed as Managing Director of United Commercial Bank with effect from 1st April, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of United Commercial Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/6/74-BO. I-2 (v)]

का०प्रा० 1159.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री के० के० पै को 1 अप्रैल, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिये सिण्डीकेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-1 (9)]

S.O. 1159.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri K. K. Pai as the Managing Director of Syndicate Bank for a further period commencing on 1st April, 1975 and ending with 30th April, 1975.

[No. F. 9/6/74-BO. I-1 (ix)]

का०प्रा० 1160.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने पश्चात् श्री के० के० पै को जिन्हें 1 अप्रैल, 1975 से सिण्डीकेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सिण्डीकेट बैंक के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० प्रो० I-2 (9)]

S.O. 1160.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri K. K. Pai, who has been re-appointed as Managing Director of Syndicate Bank with effect from 1st April, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Syndicate Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/6/74-BO. I-2 (ix)]

का० प्रा० 1161.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री पी० एफ० गुट्टा को 1 अप्रैल, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिये, यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० ओ० 1 (1) (10)]

S.O. 1161.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri P. F. Gutta as the Managing Director of Union Bank of India for a further period commencing on 1st April, 1975 and ending with 30th April, 1975.

[No. F. 9/6/74-BO. I-1(x)]

का० प्रा० 1162.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री पी० एफ० गुट्टा को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1975 से यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० ओ० 1-(2) (10)]

S.O. 1162.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri P. F. Gutta, who has been reappointed as Managing Director of Union Bank of India with effect from 1st April, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Union Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/6/74-BO. I-2(x)]

का० प्रा० 1163.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री जी० लक्ष्मीनारायण को 1 अप्रैल, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिये, इण्डियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० ओ० 1-(1) (12)]

S.O. 1163.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri G. Lakshminarayanan as the Managing Director of Indian Bank for a

further period commencing on 1st April, 1975 and ending with 30th April, 1975.

[No. F. 9/6/74-BO. I-1(xii)]

का० प्रा० 1164.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री जी० लक्ष्मीनारायण को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1975 से इण्डियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से इण्डियन बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/74-बी० ओ० 1-(2) (12)]

निर्मल चन्द्र सेनगुप्त सचिव,

S.O. 1164.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri G. Lakshminarayanan, who has been reappointed as Managing Director of Indian Bank with effect from 1st April, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Indian Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/6/74-BO. I-2(xii)]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय,

नई दिल्ली 6 मार्च 1975

आदेश

का० प्रा० 1165.—सर्वश्री आईडियल इन्स्ट्रीज, नई दिल्ली को 7,400 रुपये (सात हजार चार सौ रुपये मात्र) के लिये एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए 1400549/सी०/एक्स एक्स-52-एच-39-40/दिनांक 20-8-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण-प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ अधिकारी नई दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तबनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उन्-धारा 9 (सी० सी०) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री आईडियल इन्स्ट्रीज, नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी/ए/1400549/सी०/एक्स एक्स-52/एच/-39-40 दिनांक 22-8-74 को उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अवग से जारी की जा रही है।

[का० सं० स्पेशल सेल/30/टी डी ए/73-74]

सुधीर वर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 6th March, 1975

ORDER

S.O. 1165.—M/s. Ideal Industries, New Delhi were granted import licence No. P/A/1400549/C/XX/52/H/39-40 dated

20-8-74 for Rs. 7,400 only (Seven Thousand & Four Hundred only). They have applied for the issue of duplicate copy of Exchange Control Copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the licence has been lost.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Oath Commissioner, New Delhi. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports Control Orders 1955 dated 7-12-55 as amended from time to time the said original Exchange Control Copy of licence No. P/A/1400549/C/XX/52/H/39-40 dated 20-8-74 issued to M/s. Ideal Industries New Delhi is hereby cancelled.

A duplicate Exchange Control Copy of the said licence is being issued separately.

[F. No. SPCL/30/TDA/73-74]

SUDHIR VERMA, Dy. Chief Controller
for Chief Controller.

आवेदन

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1975

का.प्रा. 1166.—सर्वश्री दि सिरसिल्क लि. सिरपुर कागजनगर (प्रा. प्र.) को अप्रैल/मार्च, 1973 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति की कटिका 3 के अधीनन यू.के. भारत अनुकरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत एंस्टेट रेयान यार्न के विनिर्माण के लिये मशीनरी के फालतू पुर्जों के आयात के लिये 2,33,300 रुपये का एक लाइसेंस सं. पी०/डी०/2190149/आर० एम० एल०/एच०/35-36 दिनांक 22-7-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति उनके द्वारा अस्थानस्थ हो गई है लाइसेंस-धारी द्वारा आगे यह प्रतिबिम्बित किया गया है कि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराने और उसमें शेष 209365 रुपये को छोड़कर 23,935 रुपये की धनराशि का प्रयोग करने के बाद अस्थानस्थ हो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस सं. पी०/डी०/2190149 दिनांक 22-7-72 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है और निदेश देता है कि उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये। मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है। आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. रेयान 13/1/72-73 आर०एम० 6]

ए० एन० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 7th March, 1975

S.O. 1166.—M/s. The Sirsilk Ltd., Sirpur-Kaghnagar (Andhra Pradesh) were granted licence No. P/D/2190149/R/ML/44/H/35-36 dated 22-7-1972 for Rs. 2,33,300/- under U.K.-India Maintenance Loan 1971 for import of Spares for the machinery for the manufacture of Acetate Rayon Yarn subject to para 3 of ITC Policy for A/M 1973. They have requested for issue of duplicate Customs Purposes Copy of the said licence on the ground that original Customs copy has been misplaced by them. It has further been reported by the licensee that the Customs copy has been misplaced after having been registered with Bombay Customs authority and that the same has been utilised for an amount of Rs. 23,935/- leaving a balance of Rs. 2,09,365/-.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Customs

5 GI/75—5

toms Purposes copy of the licence No. P/D/2190149 dated 22-7-1972 has been misplaced/lost and directs that duplicate Customs Purposes copy of the said licence should be issued to them. The Original Customs Purposes copy is cancelled. Duplicate Customs Purposes copy of the import licence is being issued separately.

[No. Rayon 13/1/72-73/RM6]

A. N. CHATTERJEE, Dy. Chief Controller

आवेदन

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1975

का.प्रा. 1167.—सर्वश्री एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन भारत लि., काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 1 को अप्रैल-मार्च, 73 श्रवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति की कटिका 3 के अनुसार लाइसेंस धारक के कारखाने में ए० सी० एम० आर०/ए० ए० सी० कन्डक्टर के विनिर्माण के लिए उपयोग/स्थापित की गई मशीनरी के लिये स्वीकृत किस्म के फालतू पुर्जों के आयात के लिये 38,000 रुपये का एक आयात लाइसेंस संख्या पी०/डी०/2024118/आर०एम०एल०/45/एच०/35-36, दिनांक 12-10-72 स्वीकृत किया गया था।

2. फर्म ने अब उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भारत के मुख्य सेन्ट्रल बैंक के कार्यालय, कलकत्ता में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई है। आगे यह बताया गया है कि उक्त लाइसेंस कलकत्ता सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था और उस में शेष अप्रयुक्त 25,587 रुपये थे।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रक, नियम एवं क्रियाविधि हैडबुक, 1974-75 की कटिका 320 में यथा अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस संख्या: पी०/डी०/2024118/आर० एम० एल०/45/एच०/35-36 दिनांक 12-10-72 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिये। मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

4. लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. डब्ल्यू एण्ड सी 1(1)/72-73/आर० एम०-5/2]

ए० एन० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक
कुते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1975

S.O. 1167.—M/s. Aluminium Corporation of India Ltd. 7, Council House Street, Calcutta-1 were granted import licence No. P/D/2024118/R/ML/45/H/35-36 dated 12-10-1972 for Rs. 38,000/- for the import of permissible spares for the machinery for the manufacture of ACSR/AAC Conductors used/installed in the licence holder's factory as per Para 3 of I.T.C. Policy for April-March '73 period.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Exchange Control Copy of the above said import licence on the ground that the original Exchange Control Copy has been destroyed by fire that broke out in the Calcutta Main Office of the Central Bank of India. It has further been reported that the said licence had an unutilised balance of Rs. 25,587/- after having been registered with Calcutta Custom.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit as required in Para 320 of the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1974-75. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control

Copy of Import Licence No. P/D/2024118/R/ML/45/H/35-36 dated 12-10-1972 has been lost and directs that a duplicate Exchange Control Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy is cancelled.

4. The Duplicate copy of Exchange Control Copy of the licence is being issued separately.

[No. W&C/1(1)/72-73/RM. 5/2]

A. N. CHATTERJI, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

हैदराबाद, 25 फरवरी, 1975

कां०प्रा० 1168.—सर्वश्री एम्पायर प्रोडक्ट्स, 18-7-138/3 गौनीपुरा, हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से सुगंधित रसायनों की मर्चों के आयात के लिये 5,000 रु० (पांच हजार रुपये मात्र) के लिये एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एस०/1741032/सी० एक्स/एक्स/48/डब्ल्यू/37-38 दिनांक 24-9-73 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूँ कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है और निवेश देता हूँ कि आवेदक की लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये।

[फा०सं० ई०-3/एम० एस० आई०/2/ई० यू०/ए० एम०/74/हैद०]

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

Hyderabad, the 25th February, 1975

S.O. 1168.—M/s. Empire Products, 18-7-138/3, Gowli-pura, Hyderabad were granted an import licence No. P/S/1741032/C/XX48/W/37-38 dated 24-9-1973 for Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) for the item Aromatic Chemicals for import from G.C.A.

They have applied for duplicate copy of customs purpose copy of the licence on the ground that the original has been lost without having been registered with any customs authority and utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original customs purpose copy of the licence is lost. The original customs purpose copy of the licence is hereby cancelled and direct that a duplicate customs purpose copy of the licence should be issued to the applicant.

[F. No. E. 3/SSI/II/EU/AM74/Hyd.]

आदेश

कां०प्रा० 1169.—सर्वश्री एम्पायर प्रोडक्ट्स, 18-7-138/3 गौनीपुरा, हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से सुगंधित रसायनों की मर्चों के आयात के लिये 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एस०/1741034/सी०/एक्स० एक्स/48/डब्ल्यू/37-38 दिनांक 24-9-73 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूँ कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है और निवेश देता हूँ कि आवेदक की लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये।

[सं० ई०-4/एम० एस० आई०/एन० पी०/ई० यू०/ए० एम०/74/हैद०]

एम० एस० नार्दकर्णी, उ०-मुख्य नियंत्रक।

ORDER

S.O. 1169.—M/s. Empire Products 18-7-138/3, Gowli-pura, Hyderabad were granted an import licence No. P/S/1741034/C/XX48/W/37-38 dated 24-9-1973 for Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) for the item Aromatic chemicals for import from G.C.A.

They have applied for duplicate copy of customs purpose copy of the licence on the ground that the original has been lost without having been registered with any customs authority and utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original customs purpose copy of the licence is lost. The original customs purpose copy of the licence is hereby cancelled and direct that a duplicate customs purpose copy of the licence should be issued to the applicant.

[F. No. E. 4/SSI/NP/EU/AM74/Hyd.]

M. S. NADKARNI, Dy. Chief Controller.

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

मद्रास, 26 फरवरी, 1975

कां०प्रा० 1170.—सर्वश्री तिरुचिरापल्ली आटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लि०, तिरुचिरापल्ली को अप्रैल-मार्च, 1973 लाइसेंस अवधि के लिये “फोर्ट ऑनर” श्रेणी के अन्तर्गत मोटर वाहन पुर्जों के आयात के लिये 43,500 रुपये का एक आयात लाइसेंस संख्या पी०/ए०/1365091/भार०/एम०एल०/48/एम०/35-36, दिनांक 1-8-73 स्वीकृत किया गया था। स्टोर ने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस पंजीकृत कराने के बाद और 5587 रुपये तक के लिये उपयोग कर लेने के बाद खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और आवेदक को उसी की अनुलिपि प्रति जारी की जाये।

विषयाधीन लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[फा० सं० आई० टी० सी०/293-5-8-4/15/ए० एम०-73/ए०यू०]

एम० एफ० आर० बिजली, उ० मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक।

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

Madras, the 26th February, 1975

S.O. 1170.—M/s. Tiruchirapalli Automobile Spare Parts Co-operative Stores Ltd., Tiruchirapalli, were issued an import licence bearing No P/A/136509/R/ML/48/M/35-36 dated 1-8-1973 for Rs. 43,500/- for April-March, 1973 licen-

sing period for import of Motor Vehicle Parts under "Fleet Owner" Category. The stores have applied for issue of a Duplicate of the Exchange Control Copy of the licence only on the ground that the original licence has been lost/misplaced having been utilised upto Rs. 5587/-. In support of their contention they have filed an affidavit.

I am satisfied that the Exchange Control Copy of the original licence has been lost or misplaced and a Duplicate Copy of the same may be issued to the firm.

The original Exchange Central Copy of the licence in question is hereby cancelled.

[F. No. ITC/293-5-7-IV/15/AM. 73/AU]

M. F. R. BIJLI, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1975

का० प्रा० 1171.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एस-7 सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोडा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी जी एस-7 से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए आई ई	सेंटीनियर
पिलोद्रा	165	0	05	00
	169	0	27	70
	171	0	05	90
	172	0	12	60
	174	0	30	00
	175	0	00	50
	148	0	21	00
	146	0	20	20
	206	0	03	00
	205	0	03	00
	204	0	13	80
	203	0	03	00

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए आई ई	सेंटीनियर
	210	0	16	70
	212	0	01	80

[संख्या 12016/3/75-एल एण्ड एल/1]

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 22nd March, 1975

S.O. 1171.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S.-7 to C.T.F. in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from G.G.S.—7 to CTF

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are. Cen-tiare
Pilodra	165	0	05 00
	169	0	27 70
	171	0	05 90
	172	0	12 60
	174	0	30 00
	175	0	00 50
	148	0	21 00
	146	0	20 20
	206	0	03 00
	205	0	03 00
	204	0	13 80
	203	0	03 00
	210	0	16 70
	212	0	01 80

[No. 12016/3/75-L&L/I]

का० प्रा० 1172.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एस-7 सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी जी एस-7 से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात

जिला : बड़ोच

तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए	अरर इ सेंटीयर
पार्दी इंड्रीस	383	0	08	00
	355	0	16	00
	356	0	19	10
	375	0	07	60
	374	0	08	40
	373	0	02	00
	358	0	06	70
	361	0	05	50
	362	0	16	50
	335	0	02	80
	236	0	06	40
	269	0	18	00
	259	0	13	80
	257	0	10	80
	195	0	03	00
	255	0	00	50
	194	0	06	90
	196	0	11	00
	201	0	11	70
	200	0	01	50
	199	0	04	50
	188	0	05	00
	187	0	05	00
	185	0	01	05
	182	0	11	50

[सं 012016/3/75-एल एण्ड एल/2]

S.O. 1172.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S.-7 to C.T.F. in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the scheduled annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the

Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from G.G.S.—7 to CTF

State : Gujarat

District : Broach

Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are.	Cent-iare
Pardi Indris	383	0	08	00
	355	0	16	00
	356	0	19	10
	375	0	07	60
	374	0	08	40
	373	0	02	00
	358	0	06	70
	361	0	05	50
	362	0	16	50
	335	0	02	80
	236	0	06	40
	269	0	18	00
	259	0	13	80
	257	0	10	80
	195	0	03	00
	255	0	00	50
	194	0	06	90
	196	0	11	00
	201	0	11	70
	200	0	01	50
	199	0	04	50
	188	0	05	00
	187	0	05	00
	185	0	01	05
	182	0	11	50

[No. 12016/3/75-L&L/II]

का० आ० 1173.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एस-7 सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी० जी० एफ०-7 से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ौचा	तालुका : अंकलेश्वर
गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर ए आर ई सेंटीनियर
अदादा	58/बी	0 06 00
	56	0 13 20
	55	0 16 00
	54	0 07 50
	53	0 17 50
	52	0 08 50
	51	0 05 00

[संख्या 12016/3/75-एल एण्ड एन/3]

S.O. 1173.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S.-7 to C.T.F. in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the scheduled annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from G.G.S.—7 to CTF

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are.	Centiare
Adadra	58/B	0	06	00
	56	0	13	20
	55	0	16	00
	54	0	07	50
	53	0	17	50
	52	0	08	50
	51	0	05	00

[No. 12016/3/75-L&L/III]

का० प्रा० 1174.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एस-7 से टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़ाहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाचक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस

उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और रखरखाव प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौचा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनदार्थ व्यक्तिगत: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी जी एस-7 से सी टी एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : सूरत	तालुका : मंगरोल
गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर ए आर ई सेंटीनियर
कुबारदा	804	0 10 24
	803	0 00 64
	807	0 00 00
	808	0 09 47
	812	0 08 12
	814	0 00 91

[संख्या 12016/3/75-एल एण्ड एन/4]

ए ए वासुदेवन, उपसचिव

S.O. 1174.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S.-7 to C.T.F. in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the scheduled annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from G.G.S.—7 to CTF

State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are.	Centiare
Kuvarda	804	0	10	24
	803	0	00	64
	807	0	00	60
	808	0	08	47
	812	0	08	12
	114	0	00	91

[No. 12016/3/75-L&L/IV]

A. A. VASUDEVAN, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1975

का० प्रा० 117.—अतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) का अनुसरण करते हुए गुरु नानक विश्वविद्यालय ने भ्रमृतसर में मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा० प्रीतम सिंह को डा० मोहिन्दर सिंह ग्रेवाल, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था, के स्थान पर 7 अक्टूबर, 1974 से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5-13/69-एम 1 दिनांक 9 जनवरी, 1960 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित "शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक 45 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए;

"डा० प्रीतम सिंह,
प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, भ्रमृतसर"

[संख्या बी० 11013/1/74-एम०पी०टी०]

सती नायर, अवसर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING
(Department of Health)

New Delhi, the 3rd April, 1975

S.O. 1175.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Pritam Singh, Principal, Medical College, Amritsar, has been elected by the Guru Nanak University to be a member of the Medical Council of India, with effect from the 7th October, 1974 vice Dr. Mohinder Singh Grewal resigned;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", for the entry against Serial No. 45, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. Pritam Singh,
Principal,
Medical College,
Amritsar."

[F. No. V. 11013/1/74-MPT]

MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

संचार मंत्रालय
(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1975

का० प्रा० 1176.—स्थाई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने रहता टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-21/75-पी० एच० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P and T Board)

New Delhi, the 3rd April, 1975

S.O. 1176.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1975 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Rahata Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-21/75-PHB]

का० प्रा० 1177.—स्थाई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कोल्पेवाडी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-21/75-पी० एच० बी०]

S.O. 1177.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1975 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kolpewadi Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-21/75-PHB]

का० प्रा० 1178.—स्थाई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पुणतांबा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-21/75-पी० एच० बी०]

पी० सी० गुप्ता,

सहायक महानिदेशक

S.O. 1178.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1975 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pimtamla Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-21/75-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय
(नागरिक पूति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1975

का० प्रा० 1179.—केन्द्रीय सरकार, ग्रिमि संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिये मुंबई आयलसीड्स एण्ड आयल्स एक्सचेंज, लिमिटेड, मुंबई द्वारा आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर और बहु समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंगकली के तेल की ग्रिमि संविदाओं की बाबत उक्त एक्सचेंज को 25 अप्रैल, 1975 से 24 अप्रैल, 1976 तक (जिसमें दोनो दिन सम्मिलित हैं) एक वर्ष की और कालावधि के लिये एतद्वारा मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अध्वधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग समय-समय पर दिये जायेंगे।

[का० सं० 12 (2) आई० टी०/75]

यू० एस० राणा, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 29th March, 1975

S.O. 1179.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Bombay Oilseeds and Oils Exchange Limited, Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 25th April, 1975 to the 24th April, 1976 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundnut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT/75.]

U. S. RANA, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

आवेष्ट

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1975

का० आ० 1180.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एम० बी० मिनरल इण्डस्ट्रीज डाकघर मेहम्मद बाजार, जिला बिरभूम से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है—

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना बांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, अन्नवाड को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या चीनी मिट्टी की खान और छावनी के स्वामी मैसर्स एम० बी० मिनरल इण्डस्ट्रीज, डाकघर मेहम्मद बाजार, जिला बिरभूम, पश्चिम बंगाल द्वारा श्री गजाधर गुहन को पदच्युत करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-26012/11/74-एल० आर-4-डी० ओ०-3/बी०]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 1975

S.O. 1180.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Messrs M. B. Mineral Industries, Post Office Mohammad Bazar, District Birbhoom, and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the dismissal of Shri Gadadhar Guin by Messrs M.B. Mineral Industries, Owners of China Clay Mine and Washery, Post Office Mohammad Bazar, District Birbhoom, West Bengal, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-26012/11/74-LRIV-DO 3(B)]

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1975

आदेश

का० आ० 118.---यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊर्गौम के प्रबंध-तंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है:

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना बांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० सी० कन्नुर होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है?

अनुसूची

क्या भारत गोल्ड माइन्स लि०, ऊर्गौम के प्रबंध तंत्र का सर्वश्री मानिकम, कन्नन और संबंधी एन्थनी स्वामी का नुन्दीद्रुग खान के कैप लैम्प कक्ष अनुभाग से सामग्री विभाग में स्थानान्तरण करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[संख्या एल-29012/9/74-एल० आर-4-डी० ओ० 3 (बी)]

New Delhi, the 26th February, 1975

S.O. 1181.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bharat Gold Mines Limited, Oorgaum, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, with Shri M. C. Konnur as Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Bharat Gold Mines Limited, Oorgaum, is justified in transferring Sarvashri Manickam, Kannan and Anthony Swamy from Cap-Lamp Room Section of Nunddyroog Mine to Materials Department? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-29012/9/74-LR. IV-DO.3(B)]

का० आ० 1182.---यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पाइराइट्स फासफेट्स एण्ड केमिकल लिमिटेड, वेहरावूत के प्रबंध से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना बाछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या काइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, देहरादून के प्रबंधन की, माल्देओटा परियोजना, पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, देहरादून के श्री एस० एन० पाण्डेय चालक, की पदभ्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एन-29012/23/74-एल० आर०-4-डी० प्रो० 3 (बी०)]

लालकृष्ण अग्रवाल, उप-सचिव

S.O. 1182.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Dehradun, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Dehradun in dismissing Shri S. N. Pandey, Driver, in the Maldeota Project, Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Dehradun is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L-29012/23/74-LRIV-DO.3(B)]

LALFAK ZUALA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 1975

का० प्रा० 1183.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना बाछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन० द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की, बैंक की अम्बाला छावनी शाखा में लिपिक श्री शम्भू सिंह को 22 सितम्बर, 1973 से प्रोन्नति न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एन-12012/13/74-एल० आर० 3]

ORDER

New Delhi, the 7th March, 1975

S.O. 1183.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Central Bank of India in denying promotion with effect from the 22nd September, 1973, to Shri Amrik Singh, Clerk at Ambala Cantonment Branch of the Bank is justified. If not, to what relief is he entitled?

[No. L-12012/13/74-LRIII]

का० प्रा० 1184.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबद्ध में अनुसूची विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इलाहाबाद से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना बाछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इलाहाबाद बैंक के प्रबंधन की, श्री शम्भुनारायण राय को नतुनगंज (बर्दवान) में विशेष सहायक के रूप में तैनात करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एन-12012/13/74-एल० आर० 3]

S.O. 1184.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Allahabad Bank in posting Shri Shambhu Narayan Roy to Natunganj (Burdwan) as Special Assistant is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. L-12012/13/74-LRIII]

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1975

का०आ० 1185.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि हमसे उपासक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में साउथ इण्डिया बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, त्रिचूर के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी. पालनिप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

यथा साउथ इण्डिया बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय त्रिचूर के प्रबन्ध तन्त्र की 15 अक्टूबर, 1974 से कर्मचारिबुन्द के लिए मकान के लिए उधार अग्रिम धन की मात्रा को बैंक के कुल निक्षेपों के 1-1/3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत तक सीमित करके और विद्यमान तथा नए अग्रिम धनों पर व्याज की दर 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ा कर सेवा की शर्तों को बदलने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मचारिबुन्द किस अनुसूची के हकदार है?

[सं० एल-12011/2/75-डी० 2/ए०]

आर० कुजीथापदम, प्रवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 1975

S.O. 1185.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

No, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the South Indian Bank Limited, Head Office Trichur, in changing the service condition by limiting the quantum of house loan advances to members of the staff to 1 per cent instead of 1-1/3 per cent of the total deposits of the Bank and increasing the rate of interest from 7 per cent to 12 per cent on the existing and new advances with effect from 15th October, 1974 is justified? If not, to what relief are the members of the staff entitled?

[No. L-12011/2/75-DII/A]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1975

का०आ० 1186.—यतः केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड 5 GI/75—6

(6) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में, एक अधिसूचना (भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2665 दिनांक 28 सितम्बर, 1974) द्वारा ताम्बा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 सितम्बर, 1974 से छः मास की कालावधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की कालावधि के लिए और बढ़ाना अपेक्षित है

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, 28 मार्च, 1975 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का० सं० एस-11025/8/74-एल० आर०-1]

New Delhi, the 26th March, 1975

S.O. 1186.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) [being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2665 dated the 28th September, 1974] the copper mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 28th September, 1974;

And, whereas the Central Government is of opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 28th March, 1975.

[F. No. S-11025/8/74-LR.1]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1975

का०आ० 1187.—यतः केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2710 तारीख 30 सितम्बर, 1974 द्वारा यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अक्टूबर, 1974 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अप्रैल, 1975 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11025/7/75-डी०के०(ए०)]

एस० एस० सहस्रानामन, प्रवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 1975

S.O. 1187.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the

proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2710 dated the 30th September, 1974 the services in the uranium industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 20th October, 1974;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 20th April, 1975.

[No. S-11025/7/75 D.K.(A)]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 26th March, 1975

S.O. 1188.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the matter of an application under Section 33 A of the Industrial Dispute Act, 1947 from Shri Jag Narain Ram and Shri Sher Mohammad, Drivers in Intermediate Mines, which was received by the Central Government on 19th March 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Complaint No. 1 of 1973

In the matter of a Complaint under S. 33 A of the I.D. Act, 1947.

(Arising out of Ref. 7 of 1972 dt. 20-12-73)

PARTIES :

Shri Jag Narain Ram—Driver,
Shri Sher Mohammad—Driver,
Intermediate Mines : Complainant.

Vrs.

The Chief Mining Engineer,
Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd.,
P.O. Amjhore, Dist. Rohtas.

APPEARANCES :

On behalf of the Complainant : Shri B. Lal, Advocate.
On behalf of the Opp. Party : Shri T. P. Choudhury, Advocate.

State : Bihar.

Industry Phosphate.

Dhanbad, 14th March, 1975

AWARD

This case arises out of an application under section 33 A of the I.D. Act, 1947 filed by Shri Jag Narain and Sher Mohammad, Drivers under the Opp. Party Company Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd., Amjhore. It is alleged that the above Drivers have been dismissed without any permission from this Tribunal during the pendency of an Industrial adjudication and accordingly the Opp. Party has contravened S. 33 of the Industrial Disputes Act. The Opp. Party filed their written statement denying the allegation of the complainant.

The Complaint proceeded along its course and on 4-4-74 when the case was fixed the complainant remained absent without showing any cause. On the next date fixed i.e. on 18-4-74 the complainant again remained absent without showing any cause inspite of service of fresh notice on him. The Opp. party was present on that date. As the complainant remained absent on successive occasions without showing any cause I was inclined to think that he is no longer interested to prosecute his complaint and accordingly I kept the Com-

plaint for passing necessary orders. Then an application was received in this Tribunal for reviving the original complaint which was rejected.

As discussed above the complainant was given sufficient opportunity to prosecute his application but he failed to seize the same. In the circumstances the Complaint is dismissed.

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

[No. Z-20025/2/75/D.O.3(B)]

S. H. S. IYER, Section Officer (Special)

प्रादेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1975

का०प्रा० 1189.—यतः कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, नागपुर (जिसे इसके बाद उक्त कम्पनी के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) को सिलेबारा कोयला खान के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मचारियों के बीच, त्रिनिका प्रतिनिधित्व कोयला खान कर्मचारी संघ (जिसे इसके बाद संघ के नाम से निर्दिष्ट किया गया है), सिलेबारा कोयला खान करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है

और यतः उक्त कम्पनी और संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्तियों के माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को, जो उसे 18 मार्च, 1975 को मिला था, एतद्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

बीच

पक्षकार का नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले	महाप्रबन्धक कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, सिलेबारा कोयला खान
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले	कोयला खान कर्मचारी संघ, सिलेबारा कोयला खान।

पक्षकारों के 1 निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण और श्रम न्यायालय, नागपुर के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, श्री पी० डी० कुलकर्णी को माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का एतद्वारा करार किया गया है।

विवादात्मक का नाम और पता श्री पी० डी० कुलकर्णी, 68 बर्मा ले-ब्राउट, अम्माबाजारी, नागपुर-10

1. निर्दिष्ट विवादप्रस्त विषय "क्या सिलेबारा कोयला खान के वे कर्मकार, जो 4-9-1974 को और से 7-9-1974 तक काम पर नहीं थे, किसी अनुतोष के हकदार हैं और यदि हाँ, तो किस अनुतोष के।

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्दक्षित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है महाप्रबन्धक, सी एम ए एल/एन सी डी सी, 504, कांग्रेस नगर, सिलेबारा कोयला खान, नागपुर जिला नागपुर

3. यदि कोई संघ प्रस्तुत कर्म- कोयला खदान कर्मचारी संघ, सिलेवारा
कारों का प्रतिनिधित्व करता कोयला खान
हो तो उसका नाम
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित 1841
कर्मचारियों की कुल संख्या
5. विवाद द्वारा प्रभावित या 1841
सम्भाव्यतः प्रभावित होने
वाले कर्मचारियों की प्राक्कलित
संख्या

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर
बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय
के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय,
देगा।

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबन्धकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

हस्ताक्षर- हस्ताक्षर-
कोयला खदान कर्मचारी संघ (ऐटक) (ए० बी० शाह,) महाप्रबन्धक
सिलेवारा

[संख्या एल-22013/1/75/डी-3-ए]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी विशेष

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1975

S.O. 1189.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Silewara Colliery of Coal Mines Authority Limited, Nagpur (hereinafter referred to as the said Company) and their workmen represented by the Koyla Khadan Karamchhari Sangh (hereinafter referred to as the Union), Silewara Colliery.

And whereas, the said company and the Union have, by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10 A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration of the persons mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10 A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 18th March, 1975.

(Agreement)

(Under Section 10 A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of parties :

Representing employer—General Manager, Coal Mines Authority Limited, Silewara Colliery.

Representing workmen—Koyla Khadan Karmachhari Sangh, Silewara Colliery.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri P. D. Kulkarni, Retired Judge of Central Government Industrial Tribunal and Labour Court, Nagpur.

Name and address of Arbitrator—Shri P. D. Kulkarni, 68 Verma Layout, Ambazari, Nagpur-10.

(i) Specific matters in dispute :

"Are the workmen of Silewara Colliery who were not on work on and from 4-9-1974 to 7-9-1974 entitled to any relief and if so what ?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

General Manager, 504, Congress Nagar CMAL/NCDC, Silewara Nagpur, Colliery, Nagpur District.

(iii) Name of the Union, if any representing the workmen in question.

Koyla Khadan Karamchhari Sangh, Silewara Colliery

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected:
1841

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute :
1841

We further agree that decision of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing.

Representing Workmen—Koyla Khadan Karamchhari Sangh (AITUC) Silewara.

Representing Management.—A. B. SHAH, General Manager.

[No. L-22013/1/75-D-III-A]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1975

का० प्रा० 1190.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 17(81)/65-सी० एल०-1 तारीख 27 अप्रैल, 1974 को अधिष्ठातृ करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए० एस० लक्ष्मणयन के स्थान पर श्री के० ए० अन्सारी को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए समस्त आन्ध्र प्रदेश राज्य तथा पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के यानम क्षेत्र के लिए प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016(10)/74-पी० एफ०-1(ii)]

प्रसन्न चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 1975

S.O. 1190.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3096 dated the 7th September, 1972 the Central Government hereby appoints Shri K. A. Ansari to be an Inspector for the whole of the State of Andhra Pradesh and Yanam area of the Union Territory of Pondicherry for the purposes of the said Act, the Scheme and the family pension Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry, or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/10/74-PF. I(ii)]

PARSAN CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1975

New Delhi, the 1st April, 1975

क्र०अ० 1191.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 13 अप्रैल, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के सम्बन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

चिंगलेपुट जिले में सैदापेट तालुक में पेरुगुडी, कोट्टीवाक्कम्, ओगियम थोराइपाक्कम्, थोराइपाक्कम्, शोलिंगानाल्लुर, थारामानी, रामापुरम, कनकनचावादी राजस्वग्रामों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र और चिंगलेपुट जिले में श्रीपेरुम्बुदुर तालुक में मानापाक्कम् ।

[फाइल संख्या एस-38013(4)/73-एन०आई०]

ए० देव, अवर सचिव

S.O. 1191.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 13th April, 1975 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

The areas within the limits of revenue villages of Perungudi, Kottivakkam, Oggium Thoraipakkam, Thorai-pakkam, Sholinganallur, Tharamani, Ramapuram, Kandanchavadi, in Saidapet Taluk in the district of Chingleput and Manapakkam in Sriperumbudur Taluk, in the, district of Chingleput.

[F. No. S-38013(4)/73-HI]

A. DEB, Under Secy.